www.dainikjayantnews.com
कोटद्वार, शनिवार
27 जून 2026
वर्ष: 49
अंक: 63 पृष्ठ: 6
मूल्य: 2.00

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नरेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोन: 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

वेनेजुएला भारी तबाही अब तक 235 की मौत

● 4300 से ज्यादा घायल, मलबे के ढेर में जिंदगी की तलाश ● सरकार बोली-39,000 लोग लापता,नीचे से आ रहीं आवाजें

कराकस (एजेंसी)। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए दो भूकंप में अब तक 235 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। जबकि 4300 से ज्यादा लोग घायल हैं। वेनेजुएला में बुधवार यानी 25 जून को साल 1821 के काराबोबो युद्ध की याद में राष्ट्रीय अवकाश था। इसलिए ज्यादातर लोग घरों में थे और फीफा वर्ल्ड कप मैच देख रहे थे। इससे मलबे में दबने वालों की संख्या ज्यादा होने की आशंका है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मलबे के अंदर से आवाजें आ रही हैं। सरकार ने देर रात बताया कि 39 हजार से ज्यादा लोग लापता हैं। भूकंप की भयावहता की असल तस्वीर अभी आना बाकी है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से 10 हजार से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44 फीसदी आशंका है। वहीं, एक लाख लोगों के जान गंवाने की 30 फीसदी।

● **मलबे में अभी भी सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका**– वेनेजुएला में अभी भी भूकंप से तबाह हुई बिल्डिंगों के मलबे में सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। आपदा प्रभावित इलाके में अंतरराष्ट्रीय बचाव दल और मानवीय सहायता के पहुंचने के साथ ही आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि भारतीय वायुसेना के दो विमान फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री लेकर वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं।

● **राहत अभियान में जुटी टीमें**– घायलों को खून से लथपथ हालत में मलबे से बाहर निकाला गया। इनमें एक महिला सीमेंट के भारी स्लैब के नीचे फंसी हुई दिखाई दी और मलबे से उसके एक पैर का हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, बचाव दल ने काफी प्रयास के बाद उसे जीवित बाहर निकाल लिया। एक महिला अपने तीन और दस वर्षीय बच्चों के शवों को कंबलों में लपेटकर ले जाते देख फूट-फूटकर रो पड़ी और बेसुध होकर गिर गई।

संक्षिप्त समाचार

पुलिस ऑफीसर कर रहे सम्राट के खिलाफ साजिश

● भरत तिवारी एनकाउंटर पर पूर्व सांसद नागमणि का बड़ा दावा

पटना (एजेंसी)। बिहार में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी बहस छिड़ गई है। पूर्व सांसद और भाजपा नेता नागमणि ने इस एनकाउंटर को लेकर एक बेहद विवादित और चर्चित बयान दिया है, जिसने राज्य के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। नागमणि ने मारे गए भरत तिवारी के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए उसे सूबे का सबसे बड़ा गुंडा और अपराधी करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने बिहार पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जानबूझकर सम्राट चौधरी की सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर नागमणि ने कहा, सब ठीक नहीं चल रहा है। सारे पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। ये गलत है। नागमणि ने सम्राट चौधीर को लेकर कहा, कुछ पुलिस ऑफीसर भी सम्राट चौधरी जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं।

सम्राट के पक्ष में नागमणि की ताबड़तोड़ बैटिंग

सम्राट चौधरी की तारीफ में नगमणि ने खूब कसीदे गढ़े। उन्होंने कहा, लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से चुस्त और दुरुस्त करने के लिए इन्होंने (सम्राट चौधरी) कार्रवाई किया। डेवलपमेंट साइड में जो इनका इतने कम दिनों के अंदर में जो प्लानिंग है, उससे हर बिहारी खुश है। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर छोटी लड़कियों के साथ कहीं रेप होता है तो 13वीं को माला पहना दीजिए यानी उसको एनकाउंटर कर दीजिए।

ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम पहली बार सार्वजनिक

● 5 सेना, 1 एयरफोर्स का जवान पीओके में हमला किया था

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए भारतीय सशस्त्र बलों के 6 जवानों के नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किए गए हैं। इन नामों को नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 3डी वॉल पर साल 2025 के खंड में भी उनके नाम अंकित किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। भारत सरकार ने कहा था कि इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। इसके बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी।

भारत की एयरस्ट्राइक में कई पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुए थे– भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए थे। प्राइवेट कंपनी मक्सर के सैटेलाइट ने इन तबाह एयरबेस की फोटोज जारी की थीं। मक्सर ने पाकिस्तान के जिनकी फोटोज जारी की, उनमें सरगोधा, नूर खान, भोलारी और सुक्कुर के एयरबेस थे। फोटोज में साफ देखा जा सकता है कि हमले के पहले और बाद में वहां क्या स्थिति थी। सेना ने 7 मई 2025 की सुबह बताया था कि पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे।

चंदा चोरी की 'भेंट' चढ़ गए चंपत राय

● राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा, अनिल मिश्रा की भी छुट्टी

राम मंदिर केस में अब तक 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज

अयोध्या (एजेंसी)। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के तीन दिन बाद ही दो बड़े इस्तीफे हो गए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार, विश्व हिंदू परिषद ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को ट्रस्ट से इस्तीफा देने की सलाह दी है।

माना जा रहा है कि दोनों ने अपना इस्तीफा ट्रस्ट को सौंप दिया है, जिस पर आगे होने वाली ट्रस्ट की बैठक में विचार होगा। राम मंदिर ट्रस्ट ही इस पर फैसला लेगा, क्योंकि ट्रस्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है। आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को ही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसके बाद गुरुवार को मामले में केस दर्ज किया गया और 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोपियों में चंपत राय के करीबी और ड्राइवर टिन्नू यादव का नाम भी शामिल हैं। अन्य आरोपियों के नाम सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला और रमाशंकर मिश्र हैं। चंपत राय के इस्तीफे के कयास उसी समय लगाए जाने लगे थे, जब सोमवार को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

मैंने कहा था-कार्रवाई होगी और कार्रवाई शुरू हो गई

राम मंदिर मामले में बोले सीएम योगी, कांग्रेस पर जमकर बरसे

देवरिया (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है। अयोध्या के दौर पर आए अरविंद केजरीवल ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की जांच करने वाली एसआईटी पर सवाल उठाए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि, जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो रामभक्तों पर आक्षेप कर रहे हैं,अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं। सीएम योगी ने देवरिया में एक जनसभा में यह बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, एक दिल्ली से सज्जन वहां आए हैं, अयोध्या। दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष अवसर दिया,लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी,भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं दिया। सीएम योगी ने कहा कि, मैंने 19 जून को अयोध्या के दौरे पर कहा था, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा था कि एसआईटी की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। एसआइटी रिपोर्ट आई, कार्रवाई प्रारंभ हो गई है।

● टीम नितिन नवीन तैयार! जल्द होगा ऐलान

केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल के साथ शुरुआत

बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव के संकेत

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहली बार कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह फेरबदल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के संगठनात्मक बदलावों के साथ ही किया जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम के गठन को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इस बारे में बीजेपी सूत्रों ने पहले ही संकेत दिए थे कि संगठन में बड़े बदलाव जून के आखिर तक हो सकते हैं, साथ ही ये बदलाव केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल से जुड़े हो सकते हैं। गुरुवार को नितिन नबीन की कुछ राज्य मंत्रियों के साथ बातचीत के बाद फेरबदल की अटकलें और तेज हो गईं। पार्टी के लोगों का मानना है कि संगठन में फेरबदल, गुरुवार को घोषित की गई उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब होगी।

पीडीए की काट पर रहा फोकस

उत्तर प्रदेश की नई टीम में युवाओं और विभिन्न पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जातियों के प्रतिनिधित्व पर ध्यान गया है। इसे समाजवादी पार्टी की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण का जवाब माना जा रहा है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय संगठन में भी इसी तरह युवाओं, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्योंकि पार्टी युवाओं और महिलाओं के अलावा अहम जाति समूहों में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। इधर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें उस समय और तेज हो गईं जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कुछ केंद्रीय राज्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बदलाव की प्रक्रिया आखिरी दौर में है।

मोदी मंत्रिमंडल में बढ़ सकते हैं महाराष्ट्र से मंत्री!

ऑपरेशन टाइगर के बाद श्रीकांत शिंदे समेत चर्चा में पांच नाम

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में सफल ऑपरेशन टाइगर का असर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल में देखने को मिल सकता है। उद्धव ठाकरे के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के साथ आने पार्टी शिवसेना की ताकत बढ़ गई है। चर्चा है कि एक कैबिनेट बर्थ शिवसेना को मिल सकती है। मंत्री पद के लिए शिंदे के बेटे डॉ. श्रीकांत शिंदे के साथ धाराशिव से सांसद ओम राजे निंबालकर का नाम भी चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से भी कोई मंत्री बन सकती है। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तब प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आया था लेकिन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ऑफर किए जाने पर बात अटक गई थी। अब देखना है कि मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या फिर नहीं।

● **बीजेपी के चार और सहयोगी के दो मंत्री**– अभी महाराष्ट्र से कुल छह नेता केंद्र में मंत्री हैं। इनमें चार मंत्री बीजेपी और दो एनडीए के सहयोगियों के पास हैं। इनमें एक मंत्री पद एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एक मंत्री पर आरपीआई-ए के पास है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल 28 या 29 जून को होने की चर्चा है। महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल के मंत्री बनने की संभावना है। वह अभी राज्यसभा के सदस्य है और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है। अगर वे मंत्री नहीं बनते हैं तो दूसरी नाम सुनील तटकरे का है। संजय दीना पाटिल का भी नाम चर्चा में है।

इस्लाम अपना लिया तो नहीं मिलेगा ओबीसी का दर्जा

आरक्षण का लाभ भी होगा खत्म, हाईकोर्ट का फैसला

चेन्नई (एजेंसी)। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में धर्म परिवर्तन और आरक्षण को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है, जिसके तहत हिंदू धर्म की पिछड़ी, अति-पिछड़ी या अनुसूचित जाति से इस्लाम अपनाने वाले लोगों को बैकवर्ड क्लास मुस्लिम का दर्जा और आरक्षण देने की बात कही गई थी। जस्टिस जी आर स्वामीनाथन और जस्टिस पी बी बालाजी की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि कोई भी व्यक्ति इस्लाम अपनाने के बाद सिर्फ एक मुस्लिम होता है। पीठ ने कहा, कोई भी शख्स इस्लाम अपनाने के बाद सिर्फ एक मुसलमान रह जाता है, बस बात यहीं खत्म। वह बैकवर्ड क्लास मुस्लिम के दर्जे या आरक्षण का दावा कतई नहीं कर सकता। यह मामला थूथुकुडी जिले के रहने वाले समीर अहमद की याचिका के बाद सामने आया। पहले उसका नाम परमशिवम था।

परमशिवम का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। 2015 में उसने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम समीर अहमद रख लिया और मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी की। धर्म परिवर्तन के बाद समीर ने तहसीलदार के पास मुस्लिम लेब्बाई जाति का कम्युनिटी सर्टिफिकेट पाने के लिए आवेदन किया। इस जाति को तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों का दर्जा प्राप्त है।

मारपीट में घायल साथी का हालचाल पूछने एम्स पहुंचे निहंग

की संगतों से शांति बनाए रखने की अपील

ऋषिकेश। कर्णप्रयाग में निहंग सिखों व स्थानीय युवाओं के बीच हुई मारपीट में घायल एक निहंग को एम्स में भर्ती किया गया है। जिसे देखने के लिए निहंगों का एक दल एम्स पहुंचा। निहंगों ने एम्स में हो रहे उपचार को बेहतर बताया। इस संबंध में निहंगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

बीते बृहस्पतिवार को हिमाचल व उत्तराखंड की सीमा पर कुल्हाल चेक पोस्ट पर रोके गए निहंगों ने प्रशासन के समक्ष कई मांगे रखी थी। जिनमें एक मांग एम्स में भर्ती निहंग से मुलाकात की भी थी। शुक्रवार सुबह से ही आशंका जताई जा रही थी कि निहंगों का एक दल ऋषिकेश एम्स पहुंच कर यहां भर्ती निहंग से मुलाकात कर उसका हाल चाल जानेगा।

देहरादून में घुसे निहंगों का हंगामाः देर रात तक चलती रही तनातनी, फिर निहंगों को पांवटा साहिब की तरफ भेजा गया।

हांलाकि पुलिस प्रशासन और एम्स प्रशासन इस बात से इंकार करता रहा। निहंग सिखों के एक दल ने एम्स पहुंचकर यहां भर्ती निहंग से मुलाकात की पर प्रशासन ने इसे पूरी तहर गोपनीय रखा। लेकिन निहंगों के ग्रुप ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल दिया। जिसके बाद खुलासा हुआ। जिसमें निहंग एम्स में उपचार को बेहतर बता रहे हैं।

निहंग यह भी कह रहे हैं कि प्रशासन बेहतर सहयोग कर रहा हैं। निहंग वीडियों के माध्यम से सभी संगतों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं।

एक नजर

पेड़ की टहनी गिरने से हनुमान मंदिर क्षतिग्रस्त

नारायणबगड़/जिलासू। बृहस्पतिवार रात को आई आंधी से लक्ष्मी नारायण मंदिर नारायणबगड़ में पीपल के पेड़ की टहनी टूटकर हनुमान मंदिर के ऊपर जा गिरी। इससे मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर के पुजारी नारायण दत्त सती ने बताया कि हनुमान मंदिर के ऊपर टहनी गिरने से मंदिर को क्षति पहुंची है। उन्होंने बीकेटीसी से मंदिर की मरम्मत कराने की मांग की। वहीं बृहस्पतिवार रात हुई बारिश के बाद जिलासू–सरणा मार्ग पर कई स्थानों पर मलबा सड़क पर आ गया। स्थानीय संतोष ने बताया कि उनके घर के नीचे की भूमि बारिश के कारण धंस रही है जिससे मकान को खतरा बना हुआ है। इस संबंध में छह जून को लोनिवि पोखरी को लिखित आवेदन देकर सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग की थी लेकिन अब तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कंडीसौड़ में एक ट्रेड के साथ 12 साल बाद फिर शुरू हुआ आईटीआई

कंडीसौड़ (टिहरी)। थौलधार ब्लॉक मुख्यालय कंडीसौड़ में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) 12 साल बाद फिर से शुरू हो गया है। अभी वहां राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। करीब ढ़ाई करोड़ रुपये की लागत से बने भवन में नए ट्रेड खोलकर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) से संबद्ध करने की मांग की जा रही है। कंडीसौड़ में आईटीआई वर्ष 2006 में ब्लॉक कार्यालय के एक कमरे में सिलाई–बुनाई और कंप्यूटर ट्रेड के साथ शुरू किया गया था। वर्ष 2014 में वह भवन क्षतिग्रस्त होने से आईटीआई का संचालन बंद करना पड़ा। जिससे क्षेत्र के युवाओं सामने व्यावसायिक शिक्षा के लिए चंबा, जिला मुख्यालय और मैदानी क्षेत्र में जाने की मजबूरी बन गई थी। स्थानीय लोगों के प्रयास से कंडी गांव के लोगों ने आईटीआई के लिए अपनी 10 नाली जमीन दी। उसके बाद क्षेत्र के लोगों ने आईटीआई भवन बनाने की मांग शुरू की। लगातार मांग उठाने पर वर्ष 2018 में भवन निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली। जिससे लोगों को वहां पर विभिन्न ट्रेडों में जल्द ही व्यावसायिक शिक्षा मिलने की उम्मीद जगी। भवन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब एक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के साथ प्रवेश शुरू प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आईटीआई के फोरमैन विकास चंद्र ने बताया कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 20 सीटों पर अभी तक नौ प्रवेश हो गए हैं। जुलाई में और प्रवेश होने की उम्मीद है। ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि संस्थान में और ट्रेड खोलकर एनसीवीटी की मान्यता के लिए आवेदन करना चाहिए। जिससे अधिक से अधिक युवाओं को संस्थान का फायदा मिल सके।

टेंडर निरस्त नहीं होने तक जारी रहेगा जमीन बचाने का संघर्ष

कंडीसौड़ (टिहरी)। थौलधार ब्लॉक के बौर व राम गांव की चारागाह एवं पंचायती भूमि को निजी कंपनी को लीज पर दिए जाने के लिए जारी टेंडर के विरोध में आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुल्याधार में शुक्रवार को चौथे दिन भी ग्रामीण क्रमिक अनशन पर डटे रहे। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक टेंडर निरस्त नहीं किया जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

शुक्रवार को सेवानिवृत्त सूबेदार कलम सिंह कैंतुरा, दिनेश भंडारी, भाजपा महामंत्री अतर सिंह सजवाण व अतर सिंह नेगी क्रमिक अनशन पर बैठे। धरना स्थल पर हुई बैठक में ग्रमीणों ने कहा कि पैतृक जमीन की रक्षा के लिए क्षेत्रवासी किसी भी दशा में पीछे नहीं हटेंगे। आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन स्थानीय लोगों की भावनाओं की अनदेखी कर भूमि को लीज पर देने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। प्रदेश सरकार और प्रशासन से जनभावनाओं का सम्मान करते हुए भूमि की लीज के लिए जारी टेंडर तत्काल निरस्त करने की मांग दोहराई। यदि मांग की अनदेखी की गई तो आंदोलन की धार तेज की जाएगी। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अतर सिंह तोमर, पैतृक भूमि संरक्षण समिति के अध्यक्ष नत्थी सिंह कैंतुरा ने चारागाह भूमि की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

जगधार उपकेंद्र का निर्माण कार्य छह माह बाद भी नहीं हुआ शुरू

नई टिहरी। चंबा ब्लॉक के जगधार गांव में करीब 79 लाख की लागत से स्वास्थ्य विभाग का बनने वाला उपकेंद्र का भवन निर्माण छह माह बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। उपकेंद्र न बनने से क्षेत्र के लोगों में गहरा रोष बना है।

जगधार गांव में बनने वाले स्वास्थ्य उप केंद्र के निर्माण के लिए दिसंबर माह में सिंचाई विभाग टिहरी ने निविदा प्रक्रिया आमंत्रित की थी। लेकिन छह माह से अधिक समय गुजरने के बाद भी भवन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। क्षेत्र के ग्रामीणों को उम्मीद थी उपकेंद्र बनने विशेषकर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को केंद्र पर जांच और टीकाकरण की सुविधा घर भी मिलेगी लेकिन अभी तक उपकेंद्र निर्माण के नाम कुछ नहीं हो पाया है।

जांच और टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाओं को चंबा और जिला मुख्यालय की दौड़ लगानी पड़ती है। जिससे समय और आर्थिक संसाधनों का अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ता। जगधार गांव प्रस्तावित उप केंद्र का समय पर निर्माण हो जाता तो ग्रामीणों को छोटी–मोटी बीमारियों के उपचार इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। क्षेत्र के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से जल्द उपकेंद्र का निर्माण की गुहार लगाई है। सीएमओ डॉ श्याम विजय ने बताया स्वास्थ्य उपकेंद्र के भवन निर्माण कार्य शुरू करने के संबंध में सिंचाई विभाग को पूर्व में अवगत करवाया गया था। विभागीय अधिकारियों ने उपकेंद्र के निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मामले में जानकारी ली जाएगी।

दयारा बुग्याल से लापता बबीता की तलाश नाकाम

रामनगर। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल क्षेत्र के कैंप से रात में लापता हुई रामनगर की बबीता पांडे का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। काफी तलाश के बाद भी बबीता का कुछ पता नहीं चलने पर हताश स्वजन अब रामनगर चिल्किया गांव स्थित अपने घर लौट आए हैं। ऐसे में स्वजन की उम्मीदें भी टूटती जा रही हैं। बबीता को घर से गए हुए 25 जून को एक महीना पूरा हो गया है। बबीता के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। स्वजन ने अब दोबारा से मामले की सीबीआइ जांच की मांग उठाई है।

रहस्यमय तरीके से लापता हो गई बबीता

बबीता गत 25 मई को घर से ट्रैकिंग के लिए निकली थी। 29 मई को उसने उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल के बेस कैंप रैथल गांव से ट्रैकिंग शुरू की और शाम को गोई पहुंची। यहां छानी में उनके रात्रि विश्राम की व्यवस्था थी। 29 मई की रात में बबीता अपने कैंप से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। बबीता की मां अंजू पांडे व भाई हर्षित पांडे बबीता की तलाश में उत्तरकाशी क्षेत्र में ही थे।

उत्तरकाशी के जिला, स्थानीय प्रशासन की ओर से बबीता को खोजने के लिए हर प्रयास किए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बबीता की मां व भाई रामनगर घर लौट आए हैं। उन्होंने बताया कि अब सीबीआइ जांच की मांग ही अंतिम विकल्प है। बबीता के पिता गोपाल पांडे ने कहा कि बबीता को लेकर परिवार बागेश्वर धाम भी जाकर अर्जी लगाएगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया 369.66 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

जयन्त प्रतिनिधि। देहरादून : गांधी मैदान, रुद्रपुर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जनपद प्रभारी मंत्री एवं परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रदीप बत्रा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर 46.32 करोड़ की लागत से निर्मित 9 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 323.34 करोड़ की लागत के 32 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस प्रकार कुल 369.66 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब खेत बचेंगे तो जमीन बचेगी, जमीन बचेगी तो पृथ्वी बचेगी और पृथ्वी बचेगी तो जीवन सुरक्षित रहेगा।

उन्होंने किसानों से मृदा संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि भूमि केवल उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी धरती माता है, जिसका संरक्षण हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री का दायित्व किसानों के प्रथम सेवक के रूप में कार्य करना है तथा किसानों की सेवा ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है तथा कृषि क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिकाधिक लाभ लेने तथा मृदा परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देकर भूमि की उर्वरा शक्ति को संरक्षित किया जा सकता है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ भूमि सुरक्षित रखी जा सकती है। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक शिव अरोरा, त्रिलोक सिंह चीमा, बंशीधर भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर विकास शर्मा, दीपक बाली, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, हुकम सिंह कुंवर, रणजीत सिंह नामधारी, उत्तम दत्ता, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, मनोज पाल, सचिव डॉ. एस.एन. पांडे, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी, अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा, पंकज उपाध्याय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कृषक एवं आमजन उपस्थित रहे।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के लिए की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं

केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि सेब, अखरोट एवं बादाम सहित उच्च गुणवत्ता वाले फलदार पौधों के उत्पादन हेतु मुक्तेश्वर में 100 करोड़ की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। बड़ी नर्सरी स्थापित करने वालों को 4 करोड़ तथा छोटी नर्सरी स्थापित करने वालों को 2 करोड़ तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि चौबटिया (अल्मोड़ा) में 15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड के सहयोग से उत्तराखंड में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ की विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ (फेंसिंग) कार्य हेतु 65 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने के लिए 104 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा रही है, जिससे किसानों को मौसम की सटीक जानकारी समय पर उपलब्ध हो सकेगी तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ और अधिक प्रभावी ढंग से मिल सकेगा।

किसान देश की खाद्य सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था की आधारशिला

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वस्थ किसान, स्वस्थ मिट्टी तथा स्वस्थ कृषि व्यवस्था ही विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की सशक्त नींव है। उन्होंने कहा कि खेत बचाओ अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का जनआंदोलन है।

जीआईसी कठूड़ में लंबे समय से शिक्षकों के पद खाली

नई टिहरी। भिलंगना के राजकीय इंटर कॉलेज कठूड़ में लंबे समय से शिक्षकों के कई पद रिक्त पड़े होने से छात्र–छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षकों की कमी के चलते सबसे अधिक परेशानी बोर्ड परीक्षार्थियों को झेलनी पड़ती है।

हिंदाव पट्टी के जीआईसी कठूड़ में लंबे समय से प्रधानाचार्य पद के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विभाग, नागरिक शास्त्र और इतिहास विषय के प्रवक्ताओं के पद खाली चले रहे हैं। वहीं अंग्रेजी, गृह विज्ञान और संस्कृत विषय प्रवक्ताओं के पद अब तक सृजित नहीं हो पाए हैं। जिला पंचायत सदस्य विक्रम घाणता ने बताया कि विद्यालय में विगत पांच वर्ष से अधिक समय से प्रवक्ताओं के खाली चल रहे

हैं जबकि कई विषयों पर शिक्षकों के पद ही सृजित नहीं है।

बताया विद्यालय में ग्राम पंचायत कठूड़, भोना, चांजी तल्ली–मल्ली, हड़ियाणा तल्ला–मल्ला,गनवाड़ी, पुरवाल गांव सहित आसपास क्षेत्रों के करीब 170 से अधिक छात्र–छात्राएं अध्ययनरत है लेकिन शिक्षकों के कमी का असर छात्रों के भविष्य पर पड़ा रहा है। बोर्ड परीक्षा परिणाम पर भी इसका असर देखने को मिलता है। बताया क्षेत्र के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मथकुड़ी सैंण और जीआईसी अखोड़ी में भी शिक्षकों की कमी होने बनी है।

बेटी के प्रेम विवाह से नाराज पिता ने सगे भांजे को चाकू से गोदा

भगवानपुर (रुड़की)। हरिद्वार जनपद के भगवानपुर थाना क्षेत्र के हछ्मजारा गांव में शुक्रवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां बेटी के प्रेम विवाह से नाराज एक पिता ने अपने ही सगे भांजे की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपित मामा ने सेरेाह भांजे का रास्ता रोका और कहासुनी के बाद उसके पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल युवक ने देहरादून हायर सेंटर ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फरार आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

घर से भागकर किया था निकाह

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पिरान कलियर थाना क्षेत्र के रेलाहेडी गांव निवासी मुसीद का अपनी सगी ममेरी बहन (मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश निवासी मामा शहनवाज की बेटी) से प्रेम प्रसंग चल रहा था। करीब एक साल पहले मुसीद अपनी ममेरी बहन को घर से भगाकर ले गया था और दोनों ने निकाह कर लिया था। शादी के बाद से ही मुसीद अपनी पत्नी के साथ रेलाहेडी गांव में रह रहा था, लेकिन इस रिश्ते से उसका मामा शहनवाज बेहद नाराज और नाखुश था।

हरिद्वार में जमीन घोटाला: निलंबित आईएएस वरुण चौधरी समेत 10 लोगों पर कार्रवाई

देहरादून। हरिद्वार में जमीन घोटाले में निलंबित आईएएस वरुण चौधरी समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ विजिलेंस ने प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें कुछ अधिकारी और संपत्ति बेचने वाले लोग शामिल हैं। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विजिलेंस ने शुक्रवार को आरोपियों के घर व अन्य प्रतिष्ठानों पर छापे मारे। विजिलेंस की कुल आठ टीमें बनाई गई थीं जिन्होंने 10 से अधिक जगहों पर छापे मारे और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी विजिलेंस ने अपने कब्जे में लिए हैं। नगर निगम हरिद्वार ने ग्राम सराय के पास 2.3070 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। यह जमीन कृषि श्रेणी की थी जिसे मनमाने तरीके से बदलकर कमर्शियल कर दिया गया। नगर निगम ने इस जमीन को कुल 54 करोड़ रुपये में खरीदा था। जमीन क्यों खरीदी गई इसका भी कारण स्पष्ट नहीं है। शिकायत होने के बाद प्राथमिक जांच हुई और तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, नगर आयुक्त वरुण चौधरी समेत कुल नौ अफसरों को निलंबित कर दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हुई तो पिछले दिनों मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में हुई सतर्कता समिति की बैठक में आईएएस वरुण चौधरी समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ विजिलेंस में प्राथमिकी दर्ज करने की संस्तुति की गई। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को विजिलेंस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

पारंपरिक तकनीकों से संवरेंगे धारे और नौले

देहरादून। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित प्राकृतिक जलस्रोतों धारे, नौले, चाल और खाल के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय निर्माण तकनीकों को फिर से अपनाने की पहल शुरू की गई है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकास्ट) का मानना है कि सीमेंट और ईंटों के अत्यधिक उपयोग से जलस्रोतों की प्राकृतिक संरचना प्रभावित होती है, जिससे उनकी जलधारण क्षमता पर भी असर पड़ता है। इसलिए जलस्रोतों के विकास और संरक्षण में स्थानीय पत्थर, मिट्टी तथा हरी झाड़ियों जैसी पारंपरिक सामग्रियों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में यूकास्ट ने माडल परियोजना के तहत राज्यभर में 100 प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का कार्य किया। यूकास्ट के विज्ञानियों का कहना है कि पारंपरिक शैली न केवल जलस्रोतों की प्राकृतिक क्षमता को बनाए रखेगी, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता के संरक्षण में भी मददगार साबित होगी।

उत्तराखंड: पीएम सूर्य घर योजना के वेंडर्स पर कसेगा शिकंजा

देहरादून। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तराखंड में सोलर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर पंजीकृत विक्रेताओं (वेंडर्स) के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

नई व्यवस्था लागू होने से राज्य में सोलर सिस्टम लगाने वाली कंपनियों और विक्रेताओं की जवाबदेही बढ़ेगी।

उत्तराखंड में पीएम सूर्य घर योजना के तहत बड़ी संख्या में घरों में रूफटाप सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं। ऐसे में तकनीकी मानकों का पालन नहीं करने, अधूरी स्थापना, सुरक्षा खामियों और उपभोक्ता शिकायतों के मामलों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी विक्रेता के खिलाफ सोलर पीवी माड्यूल, इंवर्टर या अन्य उपकरणों की निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं का पालन नहीं करने, शिकायतों पर प्रतिक्रिया नहीं देने, वारंटी एवं तकनीकी प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराने या भुगतान लेने के बाद कार्य अधूरा छोड़ने जैसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।

उत्तराखंड में फ्लैट मालिकों के हक में लोकपाल का बड़ा फैसला

देहरादून। पैसिफिक एस्टेट रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी में अलग घरेलू बिजली कनेक्शन को लेकर चल रहे विवाद में विद्युत उपभोक्ता लोकपाल ने कहा कि मेंटेनेंस शुल्क या डेवलपमेंट चार्ज के विवाद में किसी निवासी की बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जा सकती।मामला पैसिफिक एस्टेट की निवासी अवनी शर्मा से जुड़ा है, जिन्होंने अपने फ्लैट के लिए अपने नाम पर स्वतंत्र घरेलू बिजली कनेक्शन की मांग की थी।

शिकायतकर्ता का कहना था कि सोसायटी एकल बिंदु व्यवस्था के तहत बिजली उपलब्ध करा रही थी। उनसे घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू दरों से अधिक शुल्क, मेंटेनेंस व डेवलपमेंट चार्ज लिए जा रहे थे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। शिकायतकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क जमा कर उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड से व्यक्तिगत घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। उनसे कहा गया व्यक्तिगत कनेक्शन पर विचार तभी किया जाएगा जब 50 प्रतिशत से अधिक फ्लैट मालिक इसके पक्ष में हों। शिकायतकर्ता का तर्क था कि बिजली अधिनियम–2003 और उपभोक्ता अधिकार नियमों के तहत किसी भी परिसर के मालिक या निवासी को तकनीकी व्यवहार्यता और सुरक्षा मानकों के अधीन बिजली कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकार है।यूपीसीएल ने कहा कि समूह आवास परियोजनाओं में व्यक्तिगत कनेक्शन निर्धारित शर्तों के अनुरूप ही दिए जा सकते हैं। मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने यूपीसीएल को शिकायतकर्ता के आवेदन पर नियामकीय आदेशों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही फोरम ने पैसिफिक एस्टेट रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के सचिव को स्पष्ट आदेश दिया कि शिकायतकर्ता की बिजली आपूर्ति को मेंटेनेंस या डेवलपमेंट शुल्क विवाद से नहीं जोड़ा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। मामला बिजली उपभोक्ता लोकपाल के समक्ष पहुंचा, जहां फोरम के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा गया कि आदेश नियामकीय निर्देशों के अनुरूप है। यह फैसला समूह आवासीय परियोजनाओं में रहने वाले फ्लैट मालिकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि आवश्यक सेवाओं को मेंटेनेंस या अन्य वित्तीय विवादों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता।

महिला के कपड़े चुराने वाला सनकी चोर गिरफ्तार

हल्द्वानी (नैनीताल)। नवाबी रोड स्थित महेश नगर में पिछले दिनों घर में घुसकर महिला के कपड़े चोरी करने के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

उसकी पहचान कुसुमखेड़ा समीर विहार फेज एक निवासी निकेत सिंह बिष्ट (34) के रूप में हुई है। पुलिस ने उससे चोरी किए गए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं।

मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की और आरोपित को बुधवार को पंचायत घर रोड से गिरफ्तार किया।

इससे पहले मामले में डा. सारिका गंगवार ने हीरानगर थाना पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 19 जून की देर रात अज्ञात व्यक्ति उनके मकान की दीवार फांदकर अवैध रूप से परिसर में घुस गया और उसने घर के बाहर सूख रहे कपड़ों को चोरी कर लिया। मौके से फरार हो गया।

गौला पार्किंग में सट्टेबाजी में युवक गिरफ्तार

बनभूलपुरा पुलिस ने मंगलवार रात चेकिंग के दौरान गौला पार्किंग के पास से एक व्यक्ति को सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बनभूलपुरा दिनेश सिंह फर्त्याल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से सट्टे की खाई–बाड़ी करते हुए पकड़ा।

बैजनाथ के प्राचीन पीपल पर आस्था का संकट

बागेश्वर। पहाड़ की संस्कृति में पीपल केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और प्रकृति का जीवंत प्रतीक है। गांवों में पीपल को काटना आज भी बड़ा पाप माना जाता है।

बुजुर्ग बताते हैं कि पीपल के नीचे देवताओं का वास माना जाता है और इसकी छांव में बैठकर पीढ़ियों ने जीवन के संस्कार सीखे हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस वृक्ष को बचाने की सीख पहाड़ सदियों से देता आया है, वही आज अपनी ही आस्था की आंच में झुलस रहा है।

चर्चा का विषय

विश्व प्रसिद्ध बैजनाथ धाम मंदिर परिसर में खड़ा एक प्राचीन पीपल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी मोहन परगाईं ने इंटरनेट मीडिया यानी एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए चिंता व्यक्त की है कि श्रद्धालुओं द्वारा पेड़ के तने के पास सीधे अगरबत्ती और दीपक जलाने से उसका तना धीरे–धीरे क्षतिग्रस्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राइजिंग सिटी कार्यक्रम में प्रदेश के विकास विजन को किया साझा

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रुद्रपुर के एक स्थानीय होटल सभागार में न्यूज 18 समूह द्वारा आयोजित ह्यराइजिंग सिटीह्ल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखण्ड के समग्र विकास, औद्योगिक प्रगति, आधारभूत संरचना के विस्तार, रोजगार, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था एवं सुशासन से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊधम सिंह नगर उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख ग्रोथ इंजन है और जनपद से उनका विशेष आत्मीय जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद के प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं संभावनाओं से वे भली–भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर

आज प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है तथा राज्य की आर्थिक प्रगति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखण्ड में सड़क संपर्क व्यवस्था का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ऑल वेदर रोड, एक्सप्रेस–वे और अन्य सड़क परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में यातायात पहले की अपेक्षा अधिक सुगम, सुरक्षित एवं तेज हुआ है, जिससे उद्योग, व्यापार, पर्यटन और आम जनमानस सभी को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड को दूसरे एम्स की सौगात दी गई है, जिसका निर्माण किच्छा में तेजी से चल रहा है। इसके पूर्ण होने पर केवल ऊधम सिंह नगर ही नहीं, बल्कि पूरे कुमाऊँ मंडल एवं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

एक नजर

शपथ ग्रहण समारोह 10 जुलाई को, तैयारियां तेज

श्रीनगर गढ़वाल : व्यापार सभा श्रीनगर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आगामी 10 जुलाई को स्थानीय गोला पार्क में होने वाले इस कार्यक्रम में व्यापारियों के साथ विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सम्मानित नागरिकों की मौजूदगी रहेगी। व्यापार सभा अध्यक्ष अनुज जोशी ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत होंगे। व्यापारिक संगठनों के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में व्यापार मंडल के प्रदेश संरक्षक अनिल गोयल, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा, प्रदेश महामंत्री प्रकाश मिश्रा मौजूद रहेंगे। समारोह की तैयारियों और अतिथियों को आमंत्रित करने के लिए व्यापार सभा अध्यक्ष अनुज जोशी और जिला अध्यक्ष वासुदेव कंडारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल देहरादून पहुंचा। (एजेंसी)

पांच साल की मासूम के साथ दरिंदगी, सीसीटीवी से खुला राज

पिथौरागढ, जिले में अचानक लापता हुई पांच साल की मासूम के साथ दरिंदगी होने की मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। मेडिकल रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना से हर कोई स्तब्ध है।

मामले के अनुसार बीते मंगलवार को नगर में दुकान चलाने वाले बाहरी प्रदेश के व्यापारी ने अपनी पांच साल की मासूम बच्ची के लापता होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस ने बच्ची की खोजबीन शुरू की। सीसीटीवी खंगाले गए तो एक युवक बच्ची का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता दिखा। आधी रात को बच्ची नगर के टनकपुर तिराहे के पास बदहवास और अस्त-व्यस्त हालत में मिली। ऐसे में उसके साथ दुष्कर्म होने की आशंका जताते हुए उसका मेडिकल कराया गया और आरोपी की खोजबीन शुरू हुई। जब मेडिकल रिपोर्ट मिली तो आशंका सच साबित हुई।

पुलिस के मुताबिक बच्ची के साथ अमानवीय तरीके से दरिंदगी की गई। बीते बृहस्पतिवार देर रात मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए। रात करीब 12 बजे के आसपास आरोपी रई, धनौड़ा निवासी होशियार सिंह (35) को गिरफ्तार कर लिया गया।

बी-फार्मा प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए दस्तावेज सत्यापन 30 को

नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय के भेषज विज्ञान विभाग (फार्मास्यूटिकल साइंस) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी-फार्मा) प्रथम वर्ष में प्रवेश से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। समर्थ पोर्टल पर 20 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और काउंसिलिंग के लिए आमंत्रित किया गया है।

विभागाध्यक्ष प्रो. कुमुद उपाध्याय के अनुसार दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 30 जून को सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। यह प्रक्रिया कुमाऊं विश्वविद्यालय के भीमताल स्थित ब्लॉक रोड पर जेसी बोस परिसर के भेषज विज्ञान विभाग में संपन्न होगी। काउंसिलिंग और जरूरी दस्तावेजों की सूची से संबंधित विस्तृत जानकारी अभ्यर्थियों को पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दी गई है। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद ही अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 जून को काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में दोबारा शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा।

पुलिस ने अलकनंदा से बरामद किया शव

पीपलकोटी। पुलिस ने बिरही के पास अलकनंदा में एक शव बरामद किया है। शव नदी में एक पत्थर के किनारे फंसा हुआ था। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने नदी में शव दिखने की सूचना पीपलकोटी पुलिस चौकी को दी। एसआई लक्ष्मी प्रसाद बिजल्वाण के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। एसआई लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि शव की पहचान कोड़िया निवासी रुद्र सिंह राणा (85) के रूप में हुई है।

जीआईसी सिलपाटा इंटर कॉलेज भवन का निर्माण शुरू

आदिबदरी। तहसील के जीआईसी सिलपाटा इंटर कॉलेज के नए भवन का निर्माण कार्य शुक्रवार से नावोई तोक में शुरू हो गया। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। 2.40 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण होगा जो इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा।

आदिबदरी तहसील का दूरस्थ विद्यालय सिलपाटा अब तक सीमित पांच कमरों में संचालित हो रहा था। कक्षा-कक्षों की कमी के कारण छात्र-छात्राओं को यहां बरामदे में पढ़ाई करनी पड़ती है। तीन वर्ष पहले सिलपाटा गांव के ग्रामीणों ने 12 नाली भूमि दान दी थी। पहले धन की कमी और अधिक लागत से टेंडर नहीं हो सका था। अमर उजाला ने इस संबंध में खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद कार्रवाई तेज हुई और नए भवन निर्माण के लिए 2.40 करोड़ रुपये स्वीकृत होने के बाद अब कार्य शुरू हो गया। विधायक नौटियाल ने कहा कि छात्रों की परेशानी अब दूर हो जाएगी। उन्होंने सिलपाटा को छिमटा मार्ग से जोड़ने का काम भी इसी वर्ष शुरू करने की बात कही। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता भजन सिंह नेगी, भाजपा नेता टीका प्रसाद मैखुरी, मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष विनोद नेगी, भाजपा चांदपुर गढ़ी के महामंत्री नारायण नेगी, धर्म सिंह नेगी, केदार सती, कैप्टन गैंणा रावत और पवन नेगी उपस्थित थे।

कई गांवों में पानी की सप्लाई ठप

देवाल। देवाल बाजार और आसपास के गांवों में बृहस्पतिवार शाम से पेयजल आपूर्ति ठप है। जल निगम की लापरवाही के कारण करीब पांच हजार लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं।

देवाल बाजार, आसपास की कॉलोनी, सेलखोला की करीब पांच हजार आबादी के लिए बेराधार पेयजल योजना, हनीगाड़ व गमलीगाड़ पेयजल योजना से पानी की आपूर्ति की जाती है। पहले तीनों पेयजल योजना जल संस्थान के पास थीं लेकिन कुछ माह पहले तीनों पेयजल योजना जल निगम को ट्रांसफर कर दी गईं। तब से देवाल में पेयजल की समस्या बनी है। आए दिन पेयजल आपूर्ति बंद हो जाती है। महाबीर बिष्ट, जानकी देवी, हेम चंद्र आदि उपभोक्ताओं ने जल निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार शाम से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति ठप है। लोग हैंडपंप और वाहनों से पानी ढोने के लिए मजबूर हैं। उपभोक्ताओं ने जिलाधिकारी से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की। वहीं जल निगम के अधिशासी अभियंता अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि जेई और एई को तत्काल आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं।

जख्म दे रही सड़कें, नींद में नगर निगम

कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में बदहाल पड़ी सड़कें गड्ढों की चपेट में आने से आए दिन चोटिल हो रहे वाहन चालक

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसी सड़क हो जहां आपकों गड्ढे न दिखाई दें। बदहाल पड़ी इन सड़कों पर वाहन चलाना भी एक चुनौती बन गई है। लगातार शिकायत के बाद भी सरकारी सिस्टम सड़क मरम्मत की सुध नहीं ले रहा। जबकि, पूर्व में क्षेत्रवासी बदहाल सड़कों की मरम्मत के लिए आंदोलन भी कर चुके हैं। ऐसे में कैसे व्यवस्थाएं बेहतर बनेंगी यह बड़ा सवाल है।

कोटद्वार नगर निगम के चालीस वार्डों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें बदहाल पड़ी हुई हैं। कई स्थानों पर गड्ढे इतने बड़े हैं कि दोपहिया वाहन चालकों की कमर तक टूट जा रही है। सड़क पर गड्ढों के कारण हर समय दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। सबसे बुरी स्थित मालगोदाम रोड से गाड़ीघाट होते हुए सनेह को जाने वाली माग की बनी हुई है। यही स्थिति महाविद्यालय को जोड़ने वाले शिवपुर रोड की भी बनी हुई है। देवी रोड के समीप शिब्बूनगर को जाने वाले मार्ग पर तो लोग गड्ढों के बीच डामर को खोज रहे हैं।

कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में बदहाल पड़ी सड़क

स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की वर्षा होने से सड़कें कीचड़ से भर जाती है। जिसके कारण गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे में दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। शिकायत के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं होने से लोगों में रोष बना हुआ है।

छात्र संगठनों ने निहंग सिखों पर कार्रवाई की मांग

श्रीनगर गढ़वाल : बीते दिनों यात्रा पर आए निहंगों की ओर से हुड़दंग मचाने से गुस्साए स्थानीय युवाओं और गढ़वाल विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व व वर्तमान छात्र नेताओं के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस प्रशासन से मामले में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की मांग की। युवाओं और छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन स्थानीय युवाओं की ओर से यातायात नियमों का थोड़ा सा भी उल्लंघन करने पर तुरंत चालान करता है, लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले कई लोग सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के किसी भी कोने में अगर कोई भी मर्यादा तोड़ेगा तो छात्र संगठन उसका कड़ा जवाब देंगे। इस मौके पर भाजयुमो के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर जोशी, आर्यन छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय बिष्ट, निशांत कंडारी, आयुष मियां, उत्तम भंडारी, देवकांत देवराड़ी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गौरव मोहन नेगी और अनमोल भंडारी आदि मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने और हुड़दंगियों पर लगाम कसने के लिए विशेष टीमें बनाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। (एजेंसी)

प्राथमिक विद्यालय व मंदिर में हुई चोरी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : विकासखंड एकेश्वर की रिंगवाड़स्यूं पट्टी के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़ेथ व ग्राम सभा चमाली के मंदिरों में चोरों ने सेंध लगाकर सिलिंडर, नकदी व चांदी के छत्र चोरी कर लिए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राप्रावि बड़ेथ के प्रधानाचार्य सतेंद्र सिंह रावत ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण विद्यालय बंद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संजू देवी ने उन्हें फोन पर बताया कि जब वह बाजार से घर लौट रही थीं तो उन्हें विद्यालय के समीप रास्ते से गुजरते हुए मिड डे मील कक्ष का दरवाजा खुला नजर आया। उन्होंने वहां जाकर देखा तो कक्ष का ताला टूटा हुआ था और वहां से सिलिंडर गायब था। बाकी सामान सुरक्षित था। प्रधानाचार्य ने बताया कि उनके द्वारा चोरी की घटना की प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। वहीं, विद्यालय से करीब आधा किलोमीटर के फासले पर स्थित ग्राम सभा चमाली के चंडी देवी मंदिर व आसपास के अन्य पांच मंदिरों में भी चोरों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया।

ग्रामीण अजय बिष्ट ने बताया कि चोर मंदिर के दान पात्र से लगभग 10 हजार रुपये की नकदी एवं चांदी के तीन छत्र चोरी कर ले गए हैं। मंदिर में चोरी की घटनाओं के संबंध में प्रभु सिंह रावत की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पाटीसैंण चौकी प्रभारी एसआई प्रदीप बिष्ट ने विद्यालय एवं मंदिरों में चोरी की घटनाओं की प्राथमिकी दर्ज किए जाने की पुष्टि की। हालांकि पुलिस ने चोरी में शामिल चोरों की जल्द धरपकड़ की बात कही है, लेकिन चोरी की इन घटनाओं से क्षेत्रवासियों में दहशत है। पलायन होने के कारण गांव में अब केवल बुजुर्ग ग्रामीण ही रह रहे हैं। गांव के समीप के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि रोजगार के लिए बाहर गए ग्रामीणों को चोरी की घटना के बाद से गांव में रह रहे बुजुर्ग माता-पिता की चिंता सता रही है। पुलिस प्रशासन से चोरों को शीघ्र पकड़ने की मांग की गई है।

मुहर्रम और वीकेंड की छुट्टियों में पहाड़ घूमने पहुंचे पर्यटक

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : मुहर्रम और वीकेंड की लगातार छुट्टियों के चलते मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों की ओर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। पर्यटकों के बढ़ते दबाव के कारण शुक्रवार को कोटद्वार शहर और कोटद्वार-दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिनभर लंबा जाम लगा रहा। सुबह से ही सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं और वाहन रेंग-रेंगकर आगे बढ़ते रहे।

भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। तीन दिन के अवकाश के चलते शुक्रवार को पर्यटकों की आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक रही। सुबह आठ बजे से ही शहर की प्रमुख सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ने लगा, जिससे जगह-जगह जाम की स्थिति बन गई।

यातायात प्रभावित होने की प्रमुख वजह सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन और अतिक्रमण कर लगी रेहड़ी-ठेलियां रहीं। जाम खुलवाने और यातायात सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस को दिनभर मशक्कत करनी पड़ी।

कोटद्वार की सड़कों पर लगा जाम

कोटद्वार-दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर हालत ने भी यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दीं। कई स्थानों पर सड़क का हिस्सा खोह नदी की ओर कट चुका है, जबकि जगह-जगह बने गड्ढों के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी रही। संकरी और क्षतिग्रस्त सड़क पर वाहनों के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलने से जाम की स्थिति लगातार बनी रही। वर्षाकाल के बाद से क्षतिग्रस्त पड़े इस राष्ट्रीय राजमार्ग की अब तक मरम्मत नहीं हो सकी है। नतीजतन, कोटद्वार से दुगड्डा तक करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करने में यात्रियों और पर्यटकों को एक घंटे से अधिक समय लग रहा है। स्थानीय लोगों ने हाईवे की जल्द मरम्मत कराए जाने की मांग उठाई है।

सिद्धबली-सनेह मार्ग पर बढ़ी हाथियों की धमक, रहे सावधान

सिद्धबली मंदिर के प्रवेश द्वार के समीप पहुंचे हाथी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : पिछले कुछ दिनों से सिद्धबली-सनेह मार्ग पर हाथियों की धमक ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार देर रात एक बार फिर हाथियों का झुंड सिद्धबली मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। इस दौरान मार्ग से गुजर रहे कुछ लोगों को हाथियों ने दौड़ा भी लिया।

सिद्धबली-सनेह मार्ग का अधिकांश हिस्सा जंगल से सटा होने के कारण यहां जंगली जानवरों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम हाथियों का झुंड पहले खोह नदी में पानी पीने पहुंचा और इसके बाद जंगल लौटने के बजाय ग्रास्टनगंज होते हुए सिद्धबली मंदिर के प्रवेश द्वार तक आ गया। इसी दौरान सिद्धबली-सनेह मार्ग से स्कूटी पर गुजर रहे कुछ युवकों को हाथियों ने दौड़ा लिया। हालांकि, हाथियों और युवकों के बीच पर्याप्त दूरी होने के कारण कोई हादसा नहीं हुआ। देर रात तक हाथियों का झुंड सिद्धबली धर्मशाला के आसपास घूमता रहा। वन विभाग के अनुसार हाथियों के झुंड के साथ एक शावक भी मौजूद है। ऐसे में हाथी अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क और आक्रामक हो सकते हैं।

30 जून को श्रीनगर में होगी गोष्ठी

श्रीनगर गढ़वाल : दुग्ध उत्पादन से जुड़े पशुपालकों की आय बढ़ाने और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 जून को श्रीनगर स्थित आंचल डेयरी में गोबर गैस (बायोगैस) परियोजना को लेकर एक गोष्ठी होगी। गोष्ठी में दुग्ध उत्पादक, उपभोक्ताओं और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। गोष्ठी के दौरान दुग्ध उत्पादन से जुड़े पशुपालकों से गोबर क्रय किए जाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श होगा। साथ यह भी चर्चा की जाएगी कि बायोगैस प्लांट से 500 मीटर के दायरे में रहने वाले उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन आवंटित करने की प्रक्रिया किस प्रकार संचालित की जा सकती है। आंचल डेयरी के प्रधान प्रबंधक श्रवण कुमार शर्मा ने बताया कि यह गोष्ठी पशुपालकों और उपभोक्ताओं के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। (एजेंसी)

लोगों ने उठाई स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग

श्रीनगर गढ़वाल : नगर क्षेत्र में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए व्यापारियों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने काला रोड, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग और गुरुद्वारा रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग उठाई। व्यापारियों का कहना है कि जल्द सभी व्यापारियों की ओर से नगर निगम को औपचारिक प्रस्ताव सौंपा जाएगा।

व्यापारियों का कहना है कि काला रोड, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग और गुरुद्वारा रोड पर एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। इन मार्गों पर दोपहिया वाहन चालक तेज गति से वाहन चलाते हैं जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यदि इन स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं तो वाहनों की रफ्तार नियंत्रित होगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने नगर निगम से जनहित को देखते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

व्यापारी जगमोहन कालड़ा, राहुल, सुरेश, दिनेश, दीपक और ओमप्रकाश सहित अन्य लोगों ने भी नगर निगम से जल्द स्पीड ब्रेकर निर्माण की मांग उठाई। वहीं सहायक नगर आयुक्त रविराज सिंह बंगारी ने कहा कि यदि व्यापारियों की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होता है तो निगम उस पर विचार करेगा। (एजेंसी)

समर कैंप सम्पन्न, बच्चों को दिए प्रमाण पत्र

जयन्त प्रतिनिधि।

सतपुली : भारतीय रेन बू कन कराटे डू संघ के तत्वावधान में नयारघाटी में चल रहा 15 दिवसीय समर कैम्प शुक्रवार को सम्पन्न हो गया है। इस मौके पर प्रशिक्षण ले रहे बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

समापन समारोह में मुख्य अतिथि देवेश्वरी प्रधानाध्यापिका डिवाइन लाइन पब्लिक स्कूल पाटीसैण, समाजसेवी सुदेश पोखरियाल, विशिष्ट अतिथि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष सोनू कुमार, गणेश रावत ने प्रशिक्षण ले रहे बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर जिला प्रशिक्षक विजय सिंह ने कहा कि सभी बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़कर राज्य का नाम रोशन करना चाहिए। कार्यक्रम में डॉ. विजेन्द्र सिंह उत्तराखंडी ने बच्चों को मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से बचने एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलों में प्रतिभाग करने को कहा।

मुख्य अतिथि देवेश्वरी देवी ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से बच्चों का बौद्धिक विकास, मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास होता है और बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। इस मौके पर यशपाल सिंह, प्रणव सिंह, सुनील कुमार, किशन सिंह आदि मौजूद रहे।

नशा कर देता है जीवन का नाश, इससे दूर रहें : मुकेश गौरेला

पुलिस ने बताए नशे के दुष्परिणाम, दिलाई शपथ

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल के नेतृत्व में नशामुक्त भारत पखवाड़ा के रूप में नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में छात्रों, अधिकारियों व कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जा रही है। इसके अलावा लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताकर जागरूक किया जा हा है। शुक्रवार को पाबौ चौकी प्रभारी मुकेश गैरोला की अध्यक्षता में पाबौ बाजार में नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चौकी प्रभारी ने स्थानीय लोगों, चालकों को नशे के विरूद्ध एकजुट होकर इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने व राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने हेतु शपथ दिलाई। चौकी प्रभारी ने कहा कि नशा मनुष्य जीवन का नाश करता है। बेहतर जीवन के लिए नशे से दूर रहना ही समझदारी है। कहा कि भावी पीढ़ी को नशा मुक्त समाज प्रदान करने के लिए हमें एकजुट हो कर इसको समाप्त करना होगा। वहीं नशा परिवार को तोड़ता है।

कार्यक्रम में पाबौ चौकी प्रभारी मुकेश गैरोला लोगों नशे के दुष्परिणाम बताते हुए।

नशा समाज को दूषित करता है। ऐसे में हम सभी का दायित्व है कि समाज को नशा मुक्त करने के लिए अपने-अपने स्तर पर काम करें। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने एक सबसे बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो रही है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से नशे से दूर रहने को कहा। इस मौके पर हेड कांस्टेबल अनुज कुमार सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे।

20 वर्षों की प्रतीक्षा खत्म, त्रिलोकपुर में इंटरलॉकिंग टाइल्स मार्ग का लोकार्पण

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने वार्ड नंबर 35 के त्रिलोकपुर स्थित ग्राम रामदयालपुर में नवनिर्मित इंटरलॉकिंग टाइल्स मार्ग का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और आमजन को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं।

ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि ग्राम रामदयालपुर के लोग पिछले लगभग 20 वर्षों से इस मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे थे। जंगल से सटे क्षेत्र में होने के कारण लंबे समय तक यह कार्य संभव नहीं हो सका, लेकिन लगातार प्रयासों और सरकार की जनहितकारी सोच के चलते अब यह बहुप्रतीक्षित परियोजना पूरी हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि

नए मार्ग के निर्माण से गांव के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही सिडकुल ग्रोथ सेंटर आने-जाने वाले कर्मचारियों और अन्य नागरिकों के लिए भी यह मार्ग अधिक सुरक्षित और सुगम साबित होगा। उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क बेहतर होने से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में भी वर्षों से लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा कराया जा रहा है।

उन्होंने क्षेत्रवासियों को इस विकास कार्य की शुभकामनाएं देते हुए भरोसा दिलाया कि जनहित से जुड़े कार्य भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे। इस अवसर पर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष शशिबाला केष्टवाल, पार्षद राजेंद्र बिष्ट, विधायक प्रतिनिधि प्रमोद केष्टवाल, कमल नेगी, राजेंद्र जेजेडी, अमिताभ अग्रवाल, बूथ अध्यक्ष राजेंद्र, ज्योति जखमोला, भाबर मंडल महामंत्री अभिषेक नेगी, पूर्व सैनिक कुबेर जलाल, सुदर्शन, मनीष भट्ट, राजीव डबराल, राकेश नेगी, गिरीश गौड़, अनिल गौड़ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सभी शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम तरूण कुमार पुत्र दीप चन्द अंकित है। मैं अपना नाम तरूण कुमार डबराल (TAARUN KUMAR DABRAL) पुत्र श्री दीप चन्द डबराल अंकित कराना चाहता हूं। भविष्य में मुझे तरूण कुमार डबराल (TAARUN KUMAR DABRAL) पुत्र श्री दीप चन्द डबराल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

तरूण कुमार पुत्र श्री दीप चन्द निवासी ग्राम बडेथे, पोस्ट ऑफिस काण्डाखाल, पटटी लंगूर पल्ला, तहसील कोटद्वार, जिल पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

(0541/21)

संपादकीय

नागरिकता पर भी असमंजस

हमारे देश में आम नागरिकों के लिए जारी किए जाने वाले दस्तावेजों को लेकर हमेशा से ही सवाल खड़े होते आए हैं। जहां कभी "आधार" को गलत बताया जाता था वहीं अब "आधार /" को जबरन सभी सरकारी योजनाओं और लेनदेनों से जोड़कर अनिवार्य किया गया है तो वहीं एक और फरमान के तहत "पैन कार्ड" से आधार कार्ड को लिंक करने का जबरन आदेश तो पहले ही लागू किया जा चुका है। इस सब के बावजूद भी यह दस्तावेज पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करते की क्या यह किसी भी भारतीय के लिए नागरिकता दर्शाने का वैध दस्तावेज है? किसी भी सरकारी योजना, प्रतियोगिता, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर दूसरे सरकारी कार्यों के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले नागरिकता संबंधी दस्तावेजों में पासपोर्ट को भी एक वैध प्रपत्र माना जाता है लेकिन अब इसे लेकर भी विदेश मंत्रालय ने एक नया फरमान जारी करते हुए सबको हैरान कर दिया है। विदेश मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण ने देश भर में बहस छेड़ दी कि भारतीय पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम और कानूनी प्रमाण नहीं। वर्षों से आम धारणा रही है कि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, इसलिए यह नागरिकता का सबसे मजबूत प्रमाण है लेकिन अब इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। देश में रहने वाले भारतीय व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण सिटीजन एक्ट 1955 और संविधान के प्रावधानों के तहत होता है जो दर्शाता है कि नागरिकता कोई दस्तावेज नहीं, बल्कि एक कानूनी स्थिति है, जो जन्म, वंश, पंजीकरण या दूसरे आधार से तय होती है। अब बात करें पासपोर्ट की तो विदेश मंत्रालय के अनुसार यह नागरिकता का स्पष्ट दस्तावेज नहीं है।पासपोर्ट इस बात का संकेत अवश्य है कि सरकार ने संबंधित व्यक्ति को नागरिक मानकर यह दस्तावेज जारी किया है, लेकिन यदि नागरिकता पर कानूनी विवाद खड़ा हो जाए तो केवल पासपोर्ट ही अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता है। बस यही से सवाल खड़े हो उठते हैं कि आखिर भारत में रहने वाला व्यक्ति ऐसा कौन सा दस्तावेज पेश करे जो उसकी नागरिकता को प्रमाणित करता हो। यदि पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र भी नागरिकता के अंतिम दस्तावेज नहीं हैं, तो आम नागरिक अपनी नागरिकता कैसे साबित करेगा? कानून विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में जन्म प्रमाणपत्र, माता–पिता से जुड़े दस्तावेज, नागरिकता प्रमाणपत्र और अन्य साक्ष्यों को एक साथ देखकर निर्णय लिया जाता है, लेकिन पासपोर्ट में भी तो माता–पिता तक के नाम उपलब्ध कराने पड़ते हैं। वे लोग जरूर आशंकित होंगे जो अब तक यह मान बैठे थे कि पासपोर्ट भारतीय नागरिक होने का ठोस दस्तावेज है लेकिन अब नागरिकता संबंधी दस्तावेजों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से पासपोर्ट को लेकर अपनी बात तो रख दी गई लेकिन सरकार अंतिम स्तर पर यह नहीं बता पाई की नागरिकता का वैध दस्तावेज भारतीयों के लिए क्या है? यानी स्थिति अभी भी असमंजस में है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार नागरिकता के प्रमाण संबंधी नियमों को और अधिक स्पष्ट तथा सरल बनाए, ताकि नागरिकों में भ्रम की स्थिति न रहे। लोकतंत्र में नागरिक और राज्य के बीच विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे संवेदनशील विषयों पर स्पष्टता ही उस विश्वास को मजबूत कर सकती है। सरकार को जल्द से जल्द स्पष्ट करना चाहिए कि यदि आधार कार्ड, पैन कार्ड राशन कार्ड या फिर पासपोर्ट किसी भारतीय के नागरिक होने के स्पष्ट दस्तावेज नहीं है तो फिर देश में रहने वाले लोगों की नागरिकता को पुख्ता करने के लिए कौन सा दस्तावेज सरकार की नजरों में सबसे सटीक है। यदि आधार कार्ड और पैन कार्ड भी नागरिकता दर्शन में कोई स्थान नहीं रखते तो इन्हें हर योजना लेनदेन और दूसरे सरकारी कार्यों में जबरन समायोजित करने का क्या औचित्य?

वर्दी का भय या कानून का विश्वास ?

विनोद कुमार सिंह

गोड्डा की एक घटना,पत्रकार सुरक्षा और झारखंड की कानून-व्यवस्था पर उठते गंभीर सवाल...

लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावों,सरकारों और संवैधानिक संस्थाओं से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी आंकी जाती है कि आम नागरिक स्वयं को कितना सुरक्षित,सम्मानित और स्वतंत्र महसूस करता है।जब कोई नागरिक,सामाजिक कार्यकर्ता या पत्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए भयमुक्त होकर प्रश्न पूछ सकता है,तभी लोकतंत्र वास्तव में जीवंत माना जाता है।लेकिन जब कानून की रक्षा करने वाली संस्थाओं पर ही भय पैदा करने के आरोप लगने लगें,तब लोकतंत्र के सामने गंभीर प्रश्न खड़े हो जाते हैं।

गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लालपुर गाँव में 25 जून 2026 को सामने आई एक कथित घटना ने ऐसे ही अनेक सवालों को जन्म दिया है।आरोप है कि सादे वेश में कुछ पुलिसकर्मी बिना नंबर प्लेट वाले वाहन से गाँव पहुँचे और स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिसिया रौब दिखाया। आरोप यह भी है कि एक मान्यता प्राप्तपत्रकार द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाने के बाद भी कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया।यद्यपि इन आरोपों की निष्पक्ष जाँच और पुलिस प्रशासन का पक्ष सामने आना अभी शेष है,फिर भी यह घटनाक्रम लोकतंत्र, पत्रकारिता और पुलिस जवाबदेही पर व्यापक चर्चा की माँग करता है।सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या पत्रकार भीड़ का हिस्सा है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से ह्यनहींह्ण है।पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।वह न सत्ता का प्रतिनिधि होता है और न ही विपक्ष का। उसका दायित्व जनता और शासन के बीच सूचना का सेतु बनना है।संविधान के अनुच्छेद19(1)(क)के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, पत्रकार उसी अधिकार का सामाजिक विस्तार है।उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण से जुड़े पत्रकार पिछले लगभग तीन दशकों से देश की राजधानी दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।वे अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पत्रकार संगठनों, प्रेस एसोसिएशनों तथा पत्रकार मंचों से जुड़े रहे हैं और जनसरोकार,प्रशासनिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा ग्रामीण भारत से जुड़े विषयों पर लगातार लेखन करते रहे हैं।ऐसे में यदि किसी वरिष्ठ और मान्यता प्राप्त पत्रकार के साथ भी कथित रूप से अभद्र व्यवहार या धमकी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है,तो यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति की गरिमा का नहीं रह जाता,बल्कि पत्रकारों की कार्य-स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा से भी जुड़ जाता है।भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक अवसरों पर कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। यदि पत्रकार भयमुक्त नहीं रहेगा, तो जनता तक सत्य और सूचना का प्रवाह भी बाधित होगा। इसलिए किसी पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं,बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़ा विषय बन जाता है।दूसरी ओर यह भी उतना ही सत्य है कि पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की रीढ़ होती है।झारखंड जैसे राज्य में पुलिस की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण है।राज्य लंबे समय तक नक्सलवाद,संगठित अपराध, अवैध खनन,साइबर अपराध तथा सामाजिक तनावों जैसी समस्याओं से जूझता रहा है।हाल के वर्षों में झारखंड पुलिस ने अपराध नियंत्रण और उग्रवाद विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। अपराधियों की गिरफ्तारी,अवैध हथियारों की बरामदगी और साइबर अपराध के विरुद्ध कार्रवाई पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही हैं।

गोड्डा जिला भी इससे अछूता नहीं है। जिले में समय-समय पर अवैध हथियारों,आपराधिक गिरोहों,भूमि विवादों तथा संगठित अपराधों के विरुद्ध अभियान चलाए जाते रहे हैं। ऐसे में पुलिस को कई बार त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई करनी पड़ती है,लेकिन लोकतंत्र में किसी भी कार्रवाई की वैधता केवल उसके उद्देश्य से नहीं,बल्कि उसकी प्रक्रिया से भी तय होती है। यही वह बिंदु है जहाँ नागरिक अधिकारों और पुलिस शक्तियों के बीच संतुलन आवश्यक हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता।यदि पुलिस पूछताछ करती है तो नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उससे पूछताछ करने वाला व्यक्ति कौन है और किस अधिकार के तहत कार्रवाई कर रहा है।सवाल यह भी है कि यदि पुलिस सादे वेश में कार्रवाई कर रही हो तो उसकी पहचान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है?आज के दौर में जब अपराधी भी स्वयं को पुलिस बताकर लोगों को ठगने लगे हैं,तब आम नागरिक के मन में संदेह होना स्वाभाविक है।इसलिए पारदर्शिता केवल नागरिक का अधिकार नहीं,बल्कि पुलिस प्रशासन की भी आवश्यकता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)के आँकड़े बताते हैं कि झारखंड के सामने अपराध नियंत्रण की चुनौती अभी भी बनी हुई है। हत्या,साइबर अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और आर्थिक अपराध जैसी समस्याएँ राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को अधिक अधिकार और संसाधन मिलना चाहिए, लेकिन उतनी ही मजबूती से जवाबदेही की व्यवस्था भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।यह सिद्धांत नागरिक पर भी लागू होता है और वर्दी पर भी। पुलिस की शक्ति संविधान से आती है, भय से नहीं।यदि किसी नागरिक या पत्रकार को यह महसूस हो कि उसके साथ अन्याय हुआ है,तो उसे शिकायत करने, जाँच की माँग करने और न्याय पाने का अधिकार है।आज आवश्यकता पुलिस बनाम पत्रकार की बहस की नहीं है। आवश्यकता पुलिस और पत्रकार के बीच विश्वास बहाली की है। दोनों ही लोकतंत्र की सेवा कर रहे हैं। पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है और पत्रकार उस कार्रवाई को जनता तक पहुँचाता है। दोनों का लक्ष्य अंततः जनहित ही है।यदि लालपुर की घटना में लगाए गए आरोप गलत सिद्ध होते हैं, तो इससे पुलिस की प्रतिष्ठा और मजबूत होगी।यदि कहीं किसी स्तर पर चूक या दुर्व्यवहार पाया जाता है, तो निष्पक्ष कार्रवाई से जनता का विश्वास बढ़ेगा। दोनों ही परिस्थितियों में सत्य,पारदर्शिता और विधि का शासन ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है।झारखंड पुलिस के हजारों अधिकारी और जवान कठिन परिस्थितियों में दिन-रात सेवा दे रहे हैं।उनके योगदान का सम्मान होना चाहिए।लेकिन उतना ही आवश्यक यह भी है कि आम नागरिक, पत्रकार और समाज के कमजोर वर्ग स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें।लोकतंत्र में वर्दी का सम्मान और नागरिक की गरिमा–दोनों साथ-साथ चलते हैं।

कानून का राज केवल अपराधियों को पकड़ने से स्थापित नहीं होता। कानून का राज तब स्थापित होता है जब आम आदमी बिना भय के अपने अधिकारों का उपयोग कर सके, पत्रकार बिना दबाव के प्रश्न पूछ सके और पुलिस बिना पक्षपात के कानून लागू कर सके।गोड्डा जिले की यह कथित घटना चाहे जिस निष्कर्ष तक पहुँचे,उसने एक महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य खड़ा किया है- क्या हम भय आधारित व्यवस्था चाहते हैं या विश्वास आधारित शासन?लोकतंत्र का उत्तर स्पष्ट है।वर्दी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन संविधान उससे भी ऊपर है। पत्रकार का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वह जनता की आवाज है। और सबसे बढ़कर,आम नागरिक का सम्मान होना चाहिए,क्योंकि वही लोकतंत्र का वास्तविक स्वामी है।जब वर्दी में संवेदनशीलता होगी, कलम में निर्भीकता होगी और नागरिक के मन में विश्वास होगा, तभी झारखंड की कानून-व्यवस्था वास्तव में मजबूत मानी जाएगी। यही लोकतंत्र की आत्मा है,यही संविधान की भावना है और यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति भी।

आखिर नागरिकता साबित करने के लिए कौन-सा दस्तावेज वैध?

सौरभ वार्ष्णेय

भारत में नागरिकता को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय बहस तेज हो गई है। विदेश मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बाद कि पासपोर्ट अपने-आप में नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं है, विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि नागरिकता का निर्धारण केवल किसी एक दस्तावेज से नहीं, बल्कि कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र परीक्षण के आधार पर होता है। यह विवाद केवल कानूनी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिकों के भरोसे से भी जुड़ा है। आम नागरिक का सबसे बड़ा सवाल यही है–यदि आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड और यहां तक कि पासपोर्ट भी अंतिम प्रमाण नहीं हैं, तो आखिर भारतीय नागरिकता सिद्ध कैसे होगी? लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति नागरिक का विश्वास होता है। यदि नागरिक को अपने ही अधिकारों के प्रमाण को लेकर असमंजस रहे, तो यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं कही जा सकती। इसलिए समय की मांग है कि नागरिकता प्रमाणन की प्रक्रिया स्पष्ट, सर्वसुलभ और विवाद-मुक्त बनाई जाए, ताकि किसी भी भारतीय को अपनी नागरिकता साबित करने के प्रश्न पर अनिश्चितता का सामना न करना पड़े।

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पहचान और नागरिकता एक जैसी नहीं हैं। आधार कार्ड आपकी पहचान और निवास का प्रमाण है। वोटर आईडी मतदान के अधिकार का प्रमाण है। पैन कार्ड आयकर संबंधी पहचान है। ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देता है। पासपोर्ट विदेश यात्रा और अंतरराष्ट्रीय पहचान का दस्तावेज है। लेकिन इनमें से कोई भी दस्तावेज अकेले नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जाता।

आखिर नागरिकता कैसे तय होती है? भारत में नागरिकता का आधार नागरिकता अधिनियम, 1955 है। इस कानून के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख आधार हैं–जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिककरण द्वारा, किसी क्षेत्र के भारत में विलय के आधार पर। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न उठता है तो संबंधित प्राधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों, जन्म संबंधी अभिलेखों, माता-पिता की नागरिकता, सरकारी रिकॉर्ड तथा अन्य कानूनी साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन करता है। कोई एक दस्तावेज हर परिस्थिति में निर्णायक नहीं होता।

हाल के वर्षों में जन्म प्रमाण पत्र को सबसे महत्वपूर्ण आधार दस्तावेजों में माना जाने लगा है, क्योंकि इससे जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों का रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। लेकिन जिन लोगों का जन्म दशकों पहले हुआ और जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए स्कूल प्रमाणपत्र, भूमि अभिलेख, पारिवारिक रिकॉर्ड, सरकारी सेवा अभिलेख तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेज भी परिस्थितियों के अनुसार महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकते हैं।

विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद विपक्ष ने प्रश्न उठाया कि यदि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, तो आम नागरिक किस दस्तावेज पर भरोसा करे। दूसरी ओर सत्तापक्ष का तर्क है कि दुनिया के अनेक देशों में भी पासपोर्ट नागरिकता निर्धारण का एकमात्र कानूनी आधार नहीं होता और विवाद की स्थिति में मूल नागरिकता रिकॉर्ड ही निर्णायक होते हैं। यह बहस संसद से लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों तक फैल चुकी है।

इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में आज तक ऐसा कोई एकल राष्ट्रीय नागरिकता प्रमाण-पत्र नहीं है जिसे हर स्थिति में अंतिम माना जाए। परिणामस्वरूप लोग आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों को ही नागरिकता का प्रमाण समझ लेते हैं, जबकि कानून की दृष्टि से इनकी भूमिका अलग-अलग है।

लोकतंत्र में केवल कानून होना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसका स्पष्ट और सरल संप्रेषण भी आवश्यक है। यदि नागरिकों में यह भ्रम बना रहे कि कौन-सा दस्तावेज वैध है और कौन-सा नहीं, तो इससे अनावश्यक भय और अफवाहें फैल सकती हैं।

सरकार को चाहिए कि नागरिकता प्रमाणन संबंधी एक स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करे, जिसमें बताया जाए कि विभिन्न परिस्थितियों में कौन-कौन से दस्तावेज स्वीकार्य होंगे। इससे प्रशासनिक विवाद भी कम होंगे और नागरिकों का विश्वास भी बढ़ेगा।

हर नागरिक को अपने जन्म, शिक्षा, परिवार और संपत्ति से जुड़े मूल सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और समय-समय पर उनका अद्यतन कराना भी आवश्यक है। भविष्य में किसी भी कानूनी प्रक्रिया के दौरान यही रिकॉर्ड सबसे अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं।

नागरिकता केवल एक कानूनी स्थिति नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों का आधार है। इसलिए इस विषय पर राजनीति से अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता की आवश्यकता है। नागरिकों को भ्रमित करने के बजाय सरकार को एक सरल, एकीकृत और पारदर्शी नागरिकता प्रमाणन व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।

अब केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर नागरिकता साबित करने के लिए कौन-सा दस्तावेज वैध है जिसे नागरिक प्रस्तुत कर अपनी नागरिकता सिद्ध कर सके। इस सबका एक ही निराकरण है कि केंद्र सरकार को सर्वप्रथम एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस नागरिकता पर स्पष्टता करनी चाहिए। ताकि देश में इसको लेकर किसी के मन में भ्रम न हो।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

बड़ा मिशन लेकर सेशेल्स जा रहे हैं मोदी, हिंद महासागर में भारत का मास्टरस्ट्रोक देखेगी दुनिया

नीरज कुमार दुबे

हम आपको बता दें कि सेशेल्स 115 द्वीपों वाला छोटा द्वीपीय राष्ट्र है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मोजाम्बिक चैनल के निकट उन समुद्री मार्गों पर स्थित है, जहां से विश्व व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 से 29 जून तक होने वाली सेशेल्स यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक सक्रियता और वैश्विक भूमिका को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में मोदी की भागीदारी यह संकेत देती है कि भारत अब हिंद महासागर में अपने मित्र देशों के साथ सुरक्षा, विकास और समुद्री सहयोग को और मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

हम आपको बता दें कि सेशेल्स 115 द्वीपों वाला छोटा द्वीपीय राष्ट्र है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मोजाम्बिक चैनल के निकट उन समुद्री मार्गों पर स्थित है, जहां से विश्व व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसी कारण अमेरिका, चीन और यूरोपीय शक्तियां भी इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे समय में भारत का सेशेल्स के साथ संबंध मजबूत करना हिंद महासागर में शक्ति संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण भारत द्वारा सेशेल्स तटरक्षक बल को एक तीव्र गश्ती पोत सौंपना है। इससे पहले भारत दो डोर्नियर विमान, कई गश्ती नौकाएं तथा तटीय निगरानी राडार प्रणाली भी सेशेल्स को प्रदान कर चुका है। भारतीय रक्षा कर्मियों की तैनाती और संयुक्त सैन्य अभ्यासों ने दोनों देशों के रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दी है। समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने में सेशेल्स भारत पर भरोसा करता है। यही कारण है कि यह यात्रा हिंद महासागर में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है।

हम आपको बता दें कि भारत की महासागर दृष्टि के अंतर्गत सेशेल्स को विशेष स्थान प्राप्त है। भारत अब केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार की भूमिका निभा रहा है। सेशेल्स का कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में पूर्ण सदस्य बनने का संकेत भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस समूह में भारत, मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका पहले से शामिल हैं। यदि सेशेल्स भी पूर्ण सदस्य बनता है, तो हिंद महासागर में भारत के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना और मजबूत होगी।

हम आपको बता दें कि मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के बीच होने वाली वार्ता में रक्षा सहयोग के साथ ऊर्जा, स्वास्थ्य, डिजिटल शासन, समुद्री निगरानी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। फरवरी 2026 में भारत ने सेशेल्स के लिए 175 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें ऋण सहायता और अनुदान दोनों शामिल हैं। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सौर ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। यह दर्शाता है कि भारत केवल सामरिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह विकास साझेदारी के माध्यम से भी अपने मित्र देशों के साथ दीर्घकालिक संबंध बना रहा है।

हम आपको बता दें कि भारत और सेशेल्स के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरे हैं। वर्ष 1770 में भारतीयों का पहला समूह वहां पहुंचा था। आज लगभग 15 हजार भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हैं। गुजराती और तमिल समुदाय व्यापार, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मोदी का भारतीय समुदाय से संवाद दोनों देशों के सामाजिक संबंधों को और मजबूत करेगा।

यह यात्रा वैश्विक राजनीति के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव का तेजी से विस्तार किया है। चीन की समुद्री परियोजनाएं, बंदरगाह निवेश और सामरिक उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय रही हैं। ऐसे में सेशेल्स जैसे देशों के साथ भारत का गहरा सहयोग यह स्पष्ट संदेश देता है कि हिंद महासागर में भारत अपनी पारंपरिक भूमिका को और सशक्त बना रहा है। भारत की नीति अब केवल ह्नपड़ोसी प्रथमह्व तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह ह्नग्लोबल साउथह्व के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभरना चाहता है। सेशेल्स यात्रा इसी व्यापक रणनीतिक सोच का हिस्सा है।

इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा के विशेष अधिवेशन को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। यह दोनों देशों के राजनीतिक विश्वास और घनिष्ठता का प्रतीक माना जा रहा है। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और रक्षा दल की भागीदारी भी यह दिखाती है कि दोनों देशों के संबंध केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं।

बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स यात्रा हिंद महासागर में भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति, समुद्री सुरक्षा नीति और वैश्विक प्रभाव का महत्वपूर्ण संकेत है। यह यात्रा भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना के केंद्र में स्थापित करने के साथ-साथ चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच संतुलन बनाने में भी सहायक होगी। विकास सहायता, रक्षा सहयोग, सांस्कृतिक संबंध और समुद्री साझेदारी के माध्यम से भारत यह संदेश दे रहा है कि वह हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और साझा समृद्धि का सबसे भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता है।

ट्रम्प ने संसद से 8 लाख करोड़ की फंडिंग मांगी:बोले- ईरान जंग पर हुए खर्चों की भरपाईके लिए जरूरी, संसद इसके खिलाफ

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार ने अमेरिकी संसद से 87.6 अरब डॉलर यानी करीब 8.3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग मंजूर करने की मांग की है। इसका बड़ा हिस्सा ईरान युद्ध से जुड़े खर्चों के लिए रखा गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक, यह रकम पिछले साल मंजूर किए गए करीब 1 ट्रिलियन डॉलर और अगले वित्तीय वर्ष के लिए मांगे गए 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट से अलग है। सरकार का कहना है कि यह पैसा युद्ध से जुड़े ऑपरेशन, सेना की तैयारी, हथियारों के भंडार को फिर से भरने और सीक्रेट रक्षा कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा।

वहीं, संसद में इस मांग का विरोध बढ़ रहा है। मंगलवार को सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर ट्रम्प से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा। इससे पहले ऐसा ही प्रस्ताव लोअर हाउस भी पास कर चुकी है। चार रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया।

मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान में सुधरी अमेरिका की छवि

अमेरिकी रिसर्च संस्था प्यू रिसर्च सेंटर की नई रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान युद्ध के दौरान पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम-बहुल देश रहा जहां अमेरिका को लेकर लोगों की राय बेहतर हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका-ईरान वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाने से पाकिस्तान में अमेरिका की छवि सुधरी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तानियों को ट्रम्प पर भरोसा है। सर्वे में 82% पाकिस्तानियों ने कहा कि उन्हें ट्रम्प पर भरोसा नहीं है, जबकि सिर्फ 12% ने उन पर विश्वास जताया।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 76% पाकिस्तानी मानते हैं कि अमेरिका उनके देश के आंतरिक मामलों में दखल देता है। यानी अमेरिका को लेकर सकारात्मक सोच बढ़ी है, लेकिन उसके इरादों और नेतृत्व को लेकर संदेह अब भी कायम है।

रूबियो बोले- 29-30 जून को अमेरिका-ईरान वार्ता फिर होगी

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत 29 या 30 जून को स्विट्जरलैंड में फिर शुरू हो सकती है। यह बातचीत दोनों देशों के बीच हाल में हुए संघर्षविराम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए हो रही है। रूबियो ने ईरान को चेतावनी भी दी और कहा कि अमेरिका की ओर से दी गई प्रतिबंधों में राहत अस्थायी है। अगर ईरान ने स्विट्जरलैंड वार्ता में किए गए वादे पूरे नहीं किए तो राष्ट्रपति ट्रम्प के पास प्रतिबंध फिर से लागू करने का विकल्प मौजूद है।

संक्षिप्त समाचार

सिर्फ एक पोस्ट और 7 साल की सजा, रूस में विपक्षी नेता पर बड़ी कार्रवाई

मास्को, एजेंसी। रूस में यूक्रेन युद्ध का विरोध करने वाली प्रमुख विपक्षी पार्टी याब्लोको के उप नेता मैक्सिम क्रुग्लोव को बुधवार को रूसी सेना के बारे में 'झूठ फैलाने' के आरोप में दोषी ठहराया गया और सात साल की जेल की सजा सुनाई गई। 39 वर्षीय क्रुग्लोव (मॉस्को की नगर विधानसभा के पूर्व सदस्य) को अक्टूबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर 2022 में टेलीग्राम पर दो पोस्ट करने का आरोप था, जिस वर्ष रूस ने यूक्रेन पर सैन्य अभियान शुरू किया था। अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए क्रुग्लोव ने कहा कि यह फैसला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि रूस में सार्वजनिक असहमति अब अवैध हो गई है। संक्षेप में कहा जाए तो यह असहमति पर प्रतिबंध है। उन्होंने अभियोजन पक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया कि उनके पोस्ट राजनीतिक नफरत से प्रेरित थे। क्रुग्लोव ने कहा कि उनका पूरा राजनीतिक करियर रूस में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने अदालत को बताया कि यह साबित हो गया है कि राजनीतिक असहमति को अब नफरत के समान माना जा रहा है। क्रुग्लोव ने अदालत में अंतिम बयान देते हुए कहा कि वे युद्ध के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि रूस एक दिन शांतिपूर्ण देश बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि एक ऐसा देश जिसका पड़ोसी सम्मान करें, न कि डरें, और जहां असहमति व्यक्त करना संभव हो। अदालत में पेश किए गए एक पोस्ट में यूक्रेन संघर्ष में हुई मौतों पर संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों का जिक्र था, जबकि दूसरे पोस्ट में मार्च 2022 में कीव के पास बुचा में हुई घटनाओं का उल्लेख किया गया था। यूक्रेन और पश्चिमी देशों का आरोप है कि वहां रूसी सैनिकों ने नागरिकों की हत्या की थी, जिसे मॉस्को 'मनगढ़ंत' बताता है। क्रेमलिन का कहना है कि पश्चिम के साथ 'टकराव' के दौरान रूस को एकजुट रखने के लिए सख्त सेंसरशिप कानून जरूरी हैं। याब्लोको पार्टी के नेता निकोलाई रयबाकोव ने फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया। अदालत के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लोगों को लगता है कि ऐसी सजाएं स्वीकार्य और सामान्य हैं, तो उन्हें वोट देने या याब्लोको के अलावा किसी अन्य पार्टी का समर्थन करने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। रयबाकोव ने आगे कहा कि हमारे पास अभी सिर्फ एक विकल्प है- याब्लोको को वोट देकर जो हो रहा है उसे 'ना' कहना, या किसी अन्य पार्टी को वोट देकर 'जो हो रहा है, उसे जारी रखो' कहना। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

स्नैपचैट पर मुकदमा, बच्ची से दुष्कर्म के मामले में परिवार ने कंपनी को ठहराया जिम्मेदार

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के मिसूरी राज्य में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बच्ची के माता-पिता ने सोशल मीडिया कंपनी 'स्नैप' और एक अपराधी के खिलाफ कोर्ट में केस किया है। यह मामला 12 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म से जुड़ा है। बच्ची की मुलाकात इस अपराधी से स्नैपचैट एप पर हुई थी। मुकदमे में कहा गया है कि स्नैपचैट ने अपने एप के खतरनाक फीचर्स को बंद करने से मना कर दिया है। कंपनी ने माता-पिता को उन खतरों के बारे में भी चेतावनी नहीं दी, जो इस एप के इस्तेमाल से बच्चों को हो सकते हैं।

साल 2021 में जब बच्ची 11 साल की थी, तब उसने अपने माता-पिता को बताए बिना स्नैपचैट चलाना शुरू किया था। एप पर खाता खोलने के लिए उम्र कम से कम 13 साल होनी चाहिए। लेकिन बच्ची को याद नहीं कि उसने अपनी क्या उम्र भरी थी। मुकदमे के अनुसार, बच्चों को पता है कि वे उम्र की इस शर्त को आसानी से तोड़ सकते हैं। लगभग एक साल बाद, एप ने गैब्रियल जोएल वैलेन्टिन-रियोस नाम के एक आदमी को बच्ची का दोस्त बनने का सुझाव दिया। गैब्रियल एक वयस्क था और बच्ची से उसका कोई परिचय नहीं था। एप ने बच्ची को यह नहीं बताया कि अजनबियों से जुड़ना खतरनाक हो सकता है। दोस्ती होने के बाद, गैब्रियल ने बच्ची को गंदी तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया। बच्ची यह सब नहीं चाहती थी, लेकिन स्नैपचैट की बनावट ऐसी थी कि उसके लिए इन चीजों से बचना नामुमकिन था।

किंग चार्ल्स ने तोड़ी शाही परंपरा, पहली बार अपना पर्सनल टैक्स बिल सार्वजनिक करेंगे

लंदन, एजेंसी। चार्ल्स ने पहले भी अपनी पर्सनल इनकम पर दिए गए टैक्स की जानकारी दी थी जब वह प्रिंस ऑफ़ वेल्स थे, लेकिन 2022 में महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के निधन के बाद राजा बनने के बाद यह पहली बार होगा जब वह ऐसा करेंगे। उम्मीद है कि मौजूदा प्रिंस ऑफ़ वेल्स, प्रिंस विलियम भी एक अलग ब्रीफिंग में इसी तरह का तरीका अपनाएंगे।

किंग चार्ल्स गुरुवार को अपने पर्सनल टैक्स बिल का खुलासा करने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट बनेंगे। बकिंघम पैलेस 'सॉवरेन ग्रांट' पर अपनी सालाना ब्रीफिंग के दौरान इसकी जानकारी जारी करेगा। यह कदम शाही परिवार के कामकाज में ज़्यादा पारदर्शिता की बढ़ती मांगों के बीच उठाया जा रहा है, खासकर उनके छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर के मामलों की महीनों तक हुई जांच-पड़ताल के बाद। चार्ल्स ने पहले भी अपनी पर्सनल इनकम पर दिए गए टैक्स की जानकारी दी थी जब वह प्रिंस ऑफ़ वेल्स थे, लेकिन 2022 में महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के निधन के बाद राजा बनने के बाद यह पहली बार होगा जब वह ऐसा करेंगे। उम्मीद है कि मौजूदा प्रिंस ऑफ़ वेल्स, प्रिंस विलियम भी एक अलग ब्रीफिंग में इसी तरह का तरीका अपनाएंगे। सालाना ब्रीफ़िंग में 'सॉवरेन ग्रांट' (शाही अनुदान) के बारे में भी जानकारी दी

जाएगी, जिसके ज़रिए टैक्स देने वाले लोग राजशाही को फ़ंड देते हैं। पिछले साल बकिंघम पैलेस ने 159 पेज की एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि ट्रेज़री से मिले 8.63 करोड़ पाउंड (86.3 मिलियन पाउंड) कैसे खर्च किए गए, जिसमें महल की बड़ी मरम्मत पर खर्च हुआ पैसा भी शामिल था। यह नया कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सांसद और आम लोग राजशाही के कामकाज के बारे में ज़्यादा पारदर्शिता चाहते हैं, खासकर पूर्व प्रिंस एंड्रयू से जुड़े खुलासों के बाद, जिनसे 2025 में उनके शाही खिताब छीन लिए गए थे। अब एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर के नाम से पहचाने जाने वाले एंड्रयू पर, दोषी सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ अपनी दोस्ती से जुड़े सार्वजनिक पद पर रहते हुए गलत व्यवहार के लिए जांच चल रही है। उन्हें एक बड़ी शाही जागीर भी छोड़नी पड़ी है, जहाँ वे बिना किराया दिए रह रहे थे। बीबीसी के अनुसार, महल के सूत्रों का कहना है कि राजा ने 'बेहतर समझ और जवाबदेही को बढ़ावा देने' की कोशिश के तहत अपने टैक्स भुगतान का खुलासा करने का व्यक्तिगत निर्णय लिया। माउंटबेटन-विंडसर विवाद से पहले ही, चार्ल्स ने कहा था कि वे राजशाही को छोटा करना और खर्च कम करना चाहते हैं, क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र में वंशानुगत शासक की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे।

चार्ल्स की निजी संपत्ति का अनुमान 680 मिलियन पाउंड है, जिससे वे 'संडे टाइम्स' की ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों की सालाना लिस्ट में 230वें नंबर पर हैं। हालांकि राजा या रानी को इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी चार्ल्स अपनी निजी कमाई पर स्वेच्छा से टैक्स देते हैं। महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय ने 1993 में ऐसा करना शुरू किया था, जब उससे एक साल पहले लगी भीषण आग के बाद विंडसर कैसल की मरम्मत के खर्च को लेकर जनता में नाराज़गी थी। बाद में सरकार और क्राउन के बीच एक समझौते (मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग) के ज़रिए इस व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया गया, जिसके तहत चार्ल्स को भी किसी भी अन्य टैक्सपेयर की तरह ही प्राइवेसी का अधिकार मिलता है।

आर्थिक खुशहाली का सपना देखने वाले इस देश में आज प्रवासन, राष्ट्रीय पहचान का संकट और धुर-दक्षिणपंथ का उभार वहां की राजनीति के केंद्र में है, जिसने यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद ब्रिटेन के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। ब्रेक्ज़िट जनमत संग्रह से पहले का समय राजनीतिक स्थिरता और व्यवस्थित सत्ता हस्तांतरण का दौर था, भले ही उस दौरान 2008 के वित्तीय संकट जैसी चुनौतियां थीं। इसके बाद उथल-पुथल का दौर शुरू हुआ, जिसमें छह प्रधानमंत्रियों को अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही पद छोड़ना पड़ा। इस क्रम में सबसे ताज़ा नाम कीर स्टार्मर का है, जिन्होंने 2024 के संसदीय चुनाव में भारी बहुमत हासिल करने के बावजूद, घटती लोकप्रियता और पार्टी के दबाव के कारण ब्रेक्ज़िट की 10वीं वर्षगांठ से ठीक पहले इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि 21वीं सदी की शुरुआत से ही ब्रिटिश राजनीति में लोगों की नाराज़गी बढ़ रही थी। जैसे 2003 का इराक युद्ध, 2008 का आर्थिक संकट और 2009 का खर्च घोटाला। फिर भी कई लोगों ने ब्रेक्ज़िट को वंचित लोगों के लिए अपनी निराशा ज़ाहिर करने के एक दुर्लभ मौके के तौर पर देखा, जिससे ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में कोई बड़ी दरार न आए।

बिल गेट्स ने कुबूले 3 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एपस्टीन ने की ब्लैकमेल की कोशिश

वाशिंगटन, एजेंसी। दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन और माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने निजी जिंदगी को

लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने माना है कि शादी के बाद उनके तीन महिलाओं के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। 10 जून को स हाउस ओवरसाइट कमेटी के सामने पेश होकर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। इस दौरान उन्होंने जेफरी एपस्टीन को लेकर भी कई अहम बातें बताईं।

बिल गेट्स ने बताया कि यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन उनके इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पहले से ही पूरी तरह जानता था। एपस्टीन ने इस अहम और निजी जानकारी का गलत फायदा उठाने की पूरी कोशिश की थी। वह इन अफेयर्स के जरिए बिल गेट्स को ब्लैकमेल करने की बहुत ही गहरी साजिश रच रहा था। हालांकि बिल गेट्स ने एपस्टीन के किसी भी जुर्म में शामिल होने से पूरी तरह से इनकार किया है। बिल गेट्स ने अपनी गवाही में बताया कि उनका एक रूसी ब्रिज खिलाड़ी मिला अंतोनोवा के साथ अफेयर चल रहा था। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजिसिस्ट करीमा निगमातुलिना के साथ भी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे। तीसरी महिला मेडिकल इंडस्ट्रलिस्ट एलिस जैकब्स नेसेलरॉड थीं जिनके साथ भी उनके संबंध थे। गेट्स ने साफ कहा कि ये सारे अफेयर्स उनके परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और कष्टकारी थे। बिल गेट्स ने खुलासा किया कि जेफरी एपस्टीन को उनके दो रूसी महिलाओं के साथ अफेयर्स की पूरी जानकारी मिल गई थी। एपस्टीन उनकी बेवफाई की इस अहम जानकारी का बहुत ही गलत इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि गेट्स उसके साथ दोबारा जुड़ जाएं और इसीलिए वह झूठी बातें फैलाकर दबाव बना रहा था। गेट्स ने यह भी माना कि एपस्टीन के साथ संपर्क बनाए रखना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। गेट्स ने बताया कि उनकी एपस्टीन से मुलाकात सिर्फ फिलांथ्रोपी यानी समाज सेवा के कामों पर चर्चा करने के लिए होती थी। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि एपस्टीन एक दोषी ठहराया गया व्यक्ति है और यह बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक सीमित भूमिका में उससे मिलने का वह जोखिम उठाया था। हाल ही में न्याय विभाग द्वारा जारी नए दस्तावेजों के बाद इस पुराने मामले की फिर से जांच शुरू हो गई है। कमेटी के सामने दिए गए बयान के अनुसार एपस्टीन ने गेट्स को सीधे तौर पर कभी ब्लैकमेल नहीं किया था। लेकिन उनके बीच हुए ईमेल्स को देखने से यह बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है।

फ्रांस में इबोला ने दी दस्तक, कांगो से लौटे डॉक्टर में मिला संक्रमण

डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया वैश्विक आपातकाल

पेरिस, एजेंसी। यूरोप में इबोला का पहला मामला जानलेवा इबोला वायरस ने अब यूरोप में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने देश में इबोला के पहले मामले की पुष्टि की है, जिससे पूरे महाद्वीप में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। यह मामला एक ऐसे डॉक्टर से जुड़ा है, जो हाल ही में कांगो में एक मानवीय मिशन पूरा करने के बाद फ्रांस लौटा था। संक्रमित पाए जाने के तुरंत बाद, डॉक्टर को एक विशेष आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है।

मरीज की हालत स्थिर: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संक्रमित व्यक्ति पेशे से डॉक्टर है और वह कुछ दिन पहले ही कांगो से लौटा था। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि फिलहाल मरीज की हालत स्थिर बनी हुई है।

राहत की बात यह है कि मंत्रालय ने आम जनता के लिए संक्रमण के खतरे को फिलहाल बहुत कम बताया है, क्योंकि मरीज को लक्षण दिखने के तुरंत बाद ही अलग-थलग कर दिया गया था।

इबोला के खतरनाक आंकड़े: इबोला वायरस वर्तमान में कांगो और युगांडा जैसे अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, दुनिया भर में अब तक इबोला से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,048 तक पहुंच गई है, जिनमें से 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, इस वायरस की मृत्यु दर लगभग 25.5 प्रतिशत है, जो इसे बेहद घातक बनाती है।

बुंदीबुग्यो स्ट्रेन ने बढ़ाई चिंता

सबसे बड़ी चुनौती इस बार इबोला का 'बुंदीबुग्यो' स्ट्रेन चिंता का मुख्य कारण बना हुआ है। यह इबोला वायरस का एक दुर्लभ और खतरनाक प्रकार है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस विशिष्ट स्ट्रेन के लिए फिलहाल कोई प्रमाणित वैक्सीन या पूरी तरह से प्रभावी इलाज उपलब्ध नहीं है। यह वायरस शरीर में तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी, उल्टी, दस्त और गंभीर मामलों में आंतरिक रक्तस्राव का कारण बनता है।

डब्ल्यूएचओ ने जारी किया अलर्ट

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसे 'अंतरराष्ट्रीय चिंता वाली स्वास्थ्य आपात स्थिति' घोषित कर दिया है। इसके साथ ही, अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी इसे महाद्वीपीय सुरक्षा के लिए खतरा माना है। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियों ने दुनिया भर के देशों को हवाई अड्डों और सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने की सख्त सलाह दी है ताकि संक्रमित यात्रियों की समय पर पहचान की जा सके। दक्षिण सूडान जैसे पड़ोसी देशों को वर्तमान में 'हाई रिस्क जोन' में रखा गया है।

पाकिस्तानी पति ने 10 साल तक फ्रांसीसी पत्नी को बनाया बंधक, बेटे ने कराया 'आजाद'

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक शख्स को अपनी फ्रांसीसी पत्नी और पांच बच्चों को 10 वर्ष से अधिक समय तक घर में कैद करके रखे हुए था। इस दौरान वह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता था। पुलिस ने आरोपी के बेटे की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 54 वर्षीय सिल्वी यास्मिना नामक फ्रांसीसी महिला ने पुलिस को बताया कि उनका पति बेहद हिंसक स्वभाव का है और पूरे परिवार को रोजाना शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता था।

मामला तब सामने आया जब यास्मिना के बेटों में से एक भाग निकलने में सफल हो गया और पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के

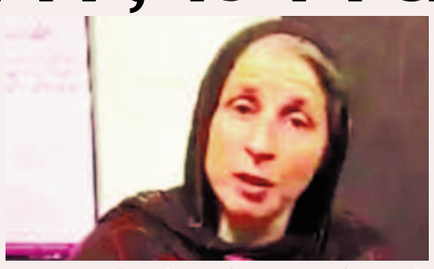

आधार पर पुलिस ने प्रांत के दूरस्थ इलाके बारा में स्थित घर पर छापेमारी की। वहां पुलिस को यास्मिना और उनके बच्चे एक तंग एवं बेहद जर्जर कमरे में कैद अवस्था में मिले। अधिकारियों ने बताया कि परिवार के सभी सदस्यों के शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने यास्मिना और उनके पांचों बच्चों को तुरंत पेशावर के एक महिला आश्रय गृह में भर्ती कराया है। परिवार अब फ्रांस लौटने की तैयारी कर रहा है। यास्मिना ने पुलिस को बताया कि 2014 में ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आने के बाद उनके पति ने पूरे परिवार को कैद कर लिया था। उन्हें किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं थी। उनके दो बड़े बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए, जबकि तीन छोटे बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए और वे कभी स्कूल नहीं जा सके। आगे यास्मिना ने बताया कि उनकी शादी 2003 में हुई थी। पाकिस्तान जाने से पहले वे ऑस्ट्रेलिया में दो बड़े बच्चों के साथ रह रहे थे। यास्मिना के अनुसार, पाकिस्तान पहुंचने के बाद परिवार का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहा।

हालांकि पुलिस ने पति की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन बताया गया है कि वह पाकिस्तानी नागरिक है।

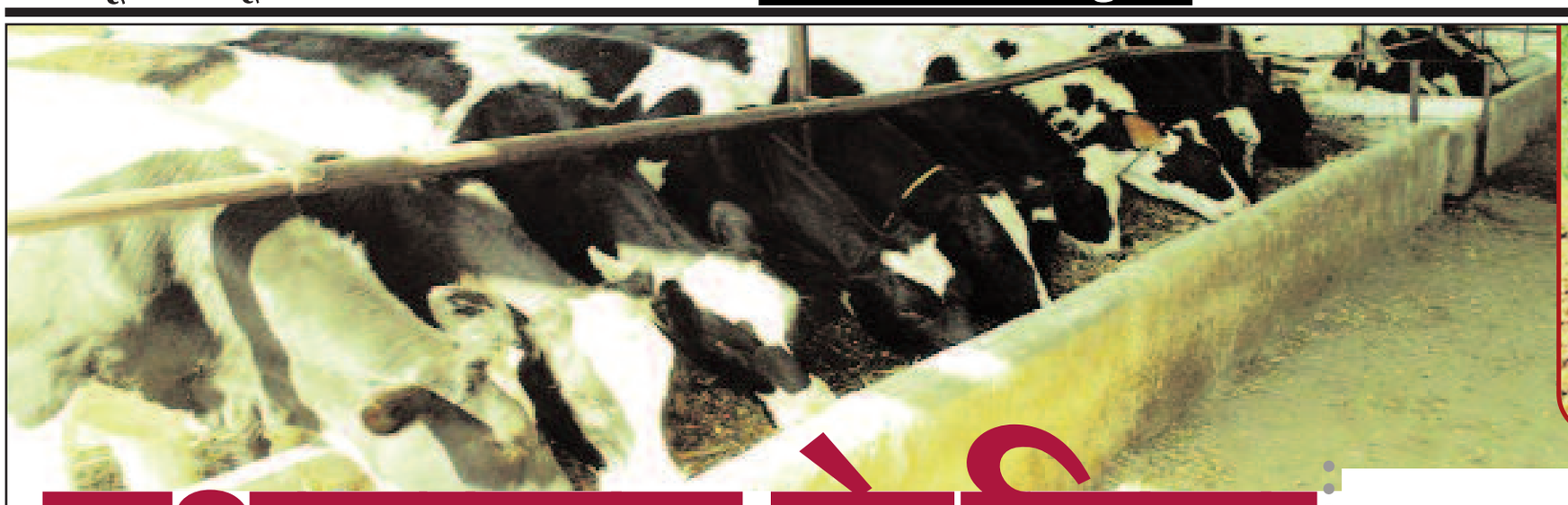

पशुपालन के बिना संभव नहीं टिकाऊ खेती

कृषि कार्य से धन अर्जन प्राचीन समय से किया जा रहा है प्राचीन सभ्यताएं स्वावलम्बी कृषि पर ही निर्भर रहीं।जब भी कृषि में स्वावलंबन समाप्त हुआ सभ्यताएं गिर गई।स्वावलम्बी कृषक बाहर के आदानों का मूल्य नहीं चुकाता है, वह उन्हें स्वयं उत्पादित करता है।स्वावलम्बन का अर्थ है पर्याप्त उत्पादन करना, पैसा कमाना तथा विपत्ति के दिनों के लिये बचाकर रखना है।भारत के किसान अपने परम्परागत ज्ञान को परिमार्जित करते हुए कृषि कार्य द्वारा मिट्टी से सोना बनाने का कार्य करता रहे, परन्तु आज पाश्चात्य् कृषि शिक्षा का प्रभाव, हरित क्रांति की चकाचौंध, कृषि के मशीनीकरण, रसायनिक खाद एवं कीटनाशकों के तात्कालिक लाभों को देखकर भारतीय किसान कृषि के स्वावलम्बन से दूर होकर रसायनिक खेती अपनाने लगा।

किसान अधिक उपज लेने के लिये आवश्यकता से अधिक उर्वरक एवं रसायनिक दवाओं का प्रयोग करने लगा जिससे उत्पादन में बढ़ोत्तरी अवश्य होती है परन्तु साथ ही साथ प्रति हेक्टेयर खर्चा भी बढता जा रहा है। इससे न केवल किसानों की आय में कमी देखी जा रही है बल्कि पर्यावरण पर भी विपरीत असर होता दिखाई दे रहा है। पिछले चार दशकों में कृषि रसायनों (खाद, कीटनाशक, नींदानाशक, और बढ़वार कारकों) और पानी के अविवेकीय अन्धाधुन्ध उपयोग ने मृदा उर्वरता, कृषि उत्पादकता के कारकों, उत्पाद गुणवत्ता एवं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाला है। रसायनिक खेती या गहन कृषि पद्धति की ओर प्रेरित किया है क्योंकि विश्व की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और खाद्यान्न की आवश्यकता में भी वृद्धि होती जा रही है। रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से कृषि योग्य भूमि में निम्ननिखित परिणाम देखने को मिले हैं।

- भूमि की सतह का सख्त होना।
- लाभप्रद जीवाणुओं की संख्या में कमी।
- भूमि की जलधारण क्षमता में कमी।
- मृदा की क्षारीयता, लवणता तथा जलागम में वृद्धि।
- भूमि में जीवाश्म की मात्रा में कमी।
- फसलों में कीट, व्याधियों व खरपतवारों की समस्या में वृद्धि ।
- भूमि की उत्पादकता में निरन्तर कमी।

उपरोक्त कारणों की वजह से आज कृषक को खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। आज हमारे विश्व की जनसंख्या लगभग 6 अरब है व सन् 2050 तक इसका 9 अरब होने का अनुमान है। लेकिन हमारी कृषि उत्पादकता बढ़ने की बजाय स्थिर हो गई है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिक आधारित या टिकाऊ खेती करने पर जोर दे रहे हैं।

टिकाऊ खेती से तात्पर्य फसल एवं पशुपालन उत्पादन के एकीकरण तंत्र से है। जो लम्बे समय तक निम्न बातें पूर्ण कर सके।

- मनुष्य के भोजन की पूर्ति कर सके।
- वातावरण की गुणवत्ता एवं प्राकृतिक संसाधनों को बचायें।
- उन सभी संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग हो जिनका पुर्नउत्पादन नहीं हो सकता है।
- भूमि की आर्थिक उपयोगिता को बनाये रखें।
- कृषक व समाज के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएं।

इस प्रकार से टिकाऊ खेती में वह सभी बातें समाहित हैं जिससे वातावारण सुधरे, आर्थिक लाभ हो एवं समाज में समानता आए। यहां पशुपालन की टिकाऊ खेती में बराबर की हिस्सेदारी है क्योंकि पशुओं की कृषि में आर्थिक उपयोगिता है, व साथ ही ये चराहाग एवं फसलों के अवशेषों आदि को मनुष्य को खाने योग्य बनाने में मदद करते हैं। टिकाऊ खेती का सबसे उत्तम उपाय है जैविक खेती। जैविक खेती से तात्पर्य है कि खेती में रसायनिक खाद, कीटनाशक व जैविक वृद्धिकारकों का उपयोग करके उत्पादन लिया जाय। जैविक खाद बनाने के लिये पशुओं की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि पशुओं से ही गोबर, मलमूत्र इत्यादि प्राप्त होंगे।

इसके अतिरिक्त मुर्गी खाद भी भूमि की उर्वराशक्ति को बढ़ाने में काफी मदद करती है, क्योंकि मुर्गी खाद में लगभग 20 प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। जिससे इस खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम लगभग 3 प्रतिशत व फास्फोरस एवं पोटाश क्रमश: 2-2 प्रतिशत होती है। वहीं सुअर के मल में नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश क्रमश: 0.7, 0.6 एवं 0.7 प्रतिशत पाए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त जैविक खेती में विभिन्न खादों जैसे गोबर व फसल अवशेष के मिश्रण से खाद (नाडेप या कम्पोष्ट खाद), गोबर गैस संयंत्र से उपलब्ध खाद एवं वर्मी कम्पोस्ट आदि का उपयोग होता है। वर्मी कम्पोस्ट केंचुए की मदद से बनने वाला खाद है। एक क्विंटल ताजा वर्मी कम्पोस्ट से भूमि को 800 ग्राम पोटेशियम प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जस्ता 0.16: तांबा 0.09 और लोहा 1.38 अनुपात होते हैं।

इसमें कुछ पादप हार्मोन्स और एन्टीबायोटिक्स भी होते हैं जो कि फसल की अच्छी पैदावार एवं पौध संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। वर्मी कम्पोस्ट की अम्लीयता क्षारीयता 6.8 से 7.2 के बीच होती है। इसमें मृदा का तापमान संतुलित रहता है व मिट्टी में पानी सोखने की प्रवृति बढती हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य उपयोग पशु का ये है कि वह जमीन जो कि अत्यंत अनउपजाऊ एवं बंजर होती है उसको भी उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं।

उपरोक्त के अलावा टिकाऊ खेती में प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। इसके लिये हम पशु ऊर्जा का उपयोग मशीनी ऊर्जा के स्थान पर कर सकते हैं। पशु ऊर्जा का उपयोग क्यों करना चाहिए यह निम्न बातों से स्पष्ट होता है-

- पशुओं का उपयोग किसान की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। यह फसलों के विविधीकरण कृषि क्षेत्र को बढाने एवं समय पर कृषि कार्यों को सम्पन्न करने में सहायक है।
- मशीनों पर आधारित उत्पादन तन्त्र कुछ ही फसलों तक सीमित रह जाता है और इस तरह विविधता को तहस-नहस कर देता है।
- पशु चलित यन्त्र सस्ते, सुलभ और गांवों में भी बनाये जा सकते हैं।
- पशु ऊर्जा का उपयोग मंहगे और अनवीनीकरण ईंधन पर होने वाले खर्च को बचाना है। पशु खेतों से ही आने वाले फसलों के अवशेष को खाकर उसे उपयोगी चीजों जैसे- दुग्ध, बायोगैस, खाद इत्यादि में बदल देते हैं, और ये भोजन के लिये मानव के प्रतियोगी भी नहीं है।
- ऊर्जा पशुओं का उपयोग पशुओं को फसलोत्पादन से जोड़ने में किसानों की मदद करता है। इस तरह पशुओं की शक्ति का फसलोत्पादन निरन्तर बनाये रखने के लिये दोहन होता रहता है।
- एक बार ट्रैक्टर या पावर टिलर की जीवन अवधि जो कि प्राय: बहुत छोटी होती है, समाप्त हो जाती है तो उसका कोई प्रयोगात्मक उपयोग नहीं रह जाता है। पशु उस पर किये गये खर्च को कई तरह से लौटाता है। वह जीवनभर व मृत्यु उपरान्त भी पशु पालकों को अनेक उपयोगी चीजें देता है। मशीनों के साथ किसानों के कर्ज में फंसने का डर बना रहता है। यदि बढ़ी ऋण सहायता से मशीनीकरण पूर्ण हो भी जाये तो अधिकतर कृषक आबादी अपनी भूमि छोड़ने के लिये बाध्य हो जायेगी। क्योंकि मशीनों की सहायता से बड़े से बड़ा क्षेत्र कुछ ही हाथों द्वारा तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि टिकाऊ खेती में पशुओं का बहुत बढ़ा योगदान है जिसकों अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

रसायनिक उर्वरकों के लाभकारी सुझाव

उर्वरकों के भरपूर लाभ कैसे लें इसके लिये निम्नलिखित बातें ध्यान रखें -

- मिट्टी परीक्षण के आधार पर नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश तत्व का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें.● मिट्टी परीक्षण के आधार पर गौण व सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग करें. ● रसायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खादों का समावेश करें.
- फसल चक्र अपनायें. ● उपयुक्त सस्य क्रियायें अपनायें.

मिट्टी परीक्षण के आधार पर गौण व सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग--जैसा कि विदित है कि हमारे द्वारा लगातार अधिक मुख्य तत्वों वाले रसायनिक उर्वरक उपयोग कर उपज में बढ़ोत्तरी की है लेकिन जमीन से गौण व सूक्ष्म पोषक तत्व जमीन में नहीं दिये जा रहे हैं. जिसके फलस्वरूप हमारी जमीन में मुख्य पोषक तत्वों के साथ-साथ गौण व सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी हो गई है। जिसमें सल्फर तत्व चौथे आवश्यक पोषक तत्व के रूप में उभर कर आया है। जिसका मुख्य कारण सघन खेती के साथ जमीन में इन पोषक तत्वों का उपयोग न करना तथा कार्बनिक पदार्थों का खेतों में न डालना है।

रसायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खादों का समावेश- परम्परागत खेती के समय रसायनिक खादों का उपयोग कम था लेकिन किसान खेती में गोबर खाद,हरी खाद एवं भूसा आदि को खेत में मिला दिया जाता था तथा सघन खेती भी नहीं होती थी जिसके कारण जमीन की जलधारण क्षमता अच्छी थी तथा पोषक तत्व भी पर्याप्त होते थे परंतु वर्तमान युग मशीनरी की खेती का युग हो गया है जिसमें पशुपालन कम होता जा रहा है किसान भाई अधिक उपज प्राप्ती के लिये मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल गये हैं जिसके परिणाम किसानों को दिखने लगे हैं कि रासायनिक खाद दिये जाने पर फसल उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार 15-20 टन गोबर खाद प्रति हेक्टर खेत में डालें.

फसल चक्र अपनायें- फसल चक्र से आशय एक ही फसल को लगातार न बोयें. पहली वर्ष यदि खरीफ में सोयाबीन और रबी में गेहूं तो दूसरी वर्ष खरीफ में मक्का एवं रबी में चना बोयें। फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश अवश्य करें. दलहनी फसल वायुमंडलीय नत्रजन को अवशोषित कर स्थिर करती है. तथा नत्रजन दलहनी फसल में नहीं देना पड़ता है.उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल,अधिक पानी वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल बोये. फसल चक्र अपनाने से उर्वरकों की क्षमता तो बढ़ती ही है साथ ही साथ कीड़े बीमारी भी कम लगती है।

उपयुक्त सस्य क्रियायें अपनायें- उपयुक्त सस्य क्रियायं अपनाने से रसायनिक उर्वरकों की दी गई मात्रा अधिक से अधिक फसल द्वारा ली जावेगी जिससे उपज भी अच्छी मिलेगी. इसके लिये कुछ मुख्य कृषि क्रियायें मुख्य हैं जो निम्नलिखित हैं.

- उपलब्ध साधनों के अनुरूप अधिक उपज देने वाली किस्म बोयें. ● बीज जनित रोगों से बचने के लिये बाबिस्टीन, थाइरम से बीज को उपचारित कर बोयें. ● किस्म की पकने की अवधि के अनुसार समय पर बुवाई करें.● उर्वरकों को सही विधि व समय पर दें. ● फसलों की बढ़वार के क्रान्तिक समय में खेत को खरपतवार रहित रखें. ● सिंचाई आवश्यकतानुसार एवं सही विधि से करें. ● रोग व बीमारियों का प्रबंधन करें. ● समय पर कटाई कर,थ्रेसिंग कर उचित भंडारण करें.

दूध के साथ रेशम उत्पादन

मिल्क विथ सिल्क सिद्धांत की जरूरत और महत्व

भारत के कई इलाकों में सिंचाई की सुविधाएँ सीमित मात्रा में होने से 50 प्रतिशत से ज्यादा खेती बारानी है। यह सर्वविदित हैं कि पिछले कुछ वर्षों से अनियमित मानसून, अमौसमी बरसात, कठोर जलवायु तथा अन्य कई कारणों से बारानी खेती बिना भरोसे की तथा नुकसानमंद साबित हो रही हैं। इससे किसानों में निराशा आर्थिक नुकसान के कारण आत्महत्या तक हो रही हैं। इस स्थिति से उबरने का एक उपाय हैं खेती से जुड़े पूरक व्यवसाय शुरू करना और उन्हें ज्यादा प्रभावी तथा ज्यादा फायदेमंद बनाने हेतु दो या तीन पूरक व्यवसायों को एक साथ करना जैसे दुग्ध व्यवसाय और रेशमकीट पालन एक साथ करना जो एक-दूसरे के पूरक हैं।

दुग्ध उत्पादन हेतु पशुपालन तथा रेशम कीट पालन हेतु मलबेरी की काश्त करना एक-दूसरों के कई तरह से पूरक हैं। पशुओं को दूध उत्पादन हेतु पौष्टिक चारा चाहिए जो उन्हें मलबेरी की पत्तियों से मिलता हैं।

इसके अलावा मलबेरी की पत्तियाँ जायकेदार पाई गई। उनकी पाचकता 70 से 90 च पाई गई। उनमें खनिज लवण 25 प्रतिशत तक पाये गये जो दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तथा पशु के स्वास्थ्य एवं प्रजनन क्षमता बरकरार रखने हेतु अत्यंत उपयुक्त हैं।

एक गाय को उसके शरीर पोषण हेतु रोजाना 7 ग्राम कैल्शियम तथा 7 ग्राम फॉस्फोरस आवश्यक होता हैं जबकि मलबेरी की पत्तियों में करीब 1.8 से 2.4 प्रतिशत कैल्शियम तथा 0.14 से 0.24 प्रतिशत फास्फोरस पाया गया हैं। इसका मतलब हैं कि अगर मलबेरी की पत्तियाँ भरपूर मात्रा में दुधारू पशु को खिलाई जाये तो उनके दूध उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी इसके अलावा उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। एक वैज्ञानिक प्रयोग में पाया गया कि खुराक और मलबेरी को पत्तियां अनुक्रम 60:40 तथा 25:75 प्रतिशत इस अनुपात में खिलाने पर गायों का दूध उत्पादन 13.2 और 13.8 लीटर प्राप्त हुआ जबकि सिर्फ खुराक खिलाने पर 14.2 लीटर था। इसका मतलब यह हुआ की मलबेरी की पत्तियाँ खिलाने से दूध उत्पादन में ज्यादा कमी नहीं आई बल्कि खुराक की मात्रा कम लगने से उसके पोषण खर्च में कमी आई यानि मलबेरी की पत्तियां खिलाने से दूध उत्पादन का धंधा किफायती होता हैं।

रेशम कीटों को डाली हुई मलबेरी की जो पत्तियां बाकी रह जाती हैं वो पत्तियाँ, डालियाँ दुधारू पशुओं को खिलाया जाये तो वह बरबाद होने से बच जाता हैं। कुछ स्थानों पर रेशम की इल्लियों के अपशिष्ट पदार्थ पर नमक का घोल डालकर वह दुधारू पशुओं को खिलाया जाता हैं।

इस प्रकार रेशम कीट पालन तथा दुग्ध व्यवसाय का आपस में घनिष्ठ नाता जोड़कर दोनों ही व्यवसाय एक साथ एक ही खेत पर कर सकते हैं। इसमें जो मजदूर होते हैं उनका उत्कृष्ठ इस्तेमाल होता हैं. रेशम कीटों द्वारा कोष निर्माण होने पर उन्हें बेचकर पैसा प्राप्त होता हैं। इसके अलावा दुग्ध व्यवसाय से दूध, खाद तथा बछड़े बेंचकर अधिक धन प्राप्त होगा और इस प्रकार किसान भाईयों को कमाई के दो स्त्रोत प्राप्त होंगे जिससे ज्यादा आर्थिक सम्पन्नता का लाभ होगा।

रेशम कीट पालन हेतु प्रशिक्षण, जानकारी, तांत्रिक मार्गदर्शन, रेशम उद्योग, संचालनालय से प्राप्त होते हैं तथा दुग्ध व्यवसाय के विषय में जानकारी प्रशिक्षण तथा तांत्रिक मार्गदर्शन हर जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र, जिले के पशुपालन विभाग, कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित पशुपालन एवं दुग्ध शास्त्र विभाग आदि जगह से प्राप्त कर सकते हैं।

ध्यान रहे, पूरक व्यवसाय के बिना किसान भाईयों की सही मायने में उन्नति नहीं हो सकती अत: पूरक व्यवसाय अवश्य अपनाएं और अपनी आर्थिक उन्नति हासिल करें.

संक्षिप्त समाचार

.सिडकुल चौराहे पर अमोनिया गैस रिसाव, राहगीरों में मची अफरा—तफरी

रुद्रपुर, शहर में सिडकुल चौराहे के पास शुक्रवार सुबह अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। सुबह पौने सात बजे एक टैंकर से गैस छलकने लगी। इससे चौराहे पर गैस की तेज गंध फैल गई और राहगीरों में अफरा–तफरी मच गई।

अग्निशमन अधिकारी महेश चंद्र स्वयं टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बजाज कंपनी के साथ मिलकर चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। अग्निशमन वाहन से पंप करके सड़क की धुलाई की गई। इस संयुक्त अभियान में स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद था। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (डीडीओएम) की टीमें भी घटनास्थल पर उपस्थित थीं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी कटारिया ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अग्निशमन इकाई को निर्देश दिए कि अमोनिया गैस पूरी तरह समाप्त होने के बाद ही अग्निशमन केंद्र लौटें।

नीट पेपर लीक से नाराज कांग्रेसियों ने फूंका प्रधानमंत्री का पुतला

बाजपुर। नीट और यूजीसी नेट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। उसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में दिया।

बृहस्पतिवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पवन शर्मा, नगर अध्यक्ष सत्यवान गर्ग की अगुवाई में कार्यकर्ता रामलीला मैदान में एकत्र हुए। यहां जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय गेट पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर विरोध जताया।

उन्होंने एसडीएम की गैरमौजूदगी में कार्यालय में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। उन्होंने पेपर लीक होने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने और पेपर लीक के कारण आत्मघाती कदम उठाने वाले युवाओं के परिजनों को एक–एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की।

लोन फर्जीवाड़े में शाखा प्रबंधक समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी

खटीमा। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण लेने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दंपती और कंपनी के शाखा प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस्लामनगर निवासी मैराज बी ने तहरीर देकर बताया कि उन्होंने वर्ष 2016 में सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड (एससीएनएल) की खटीमा शाखा से ऋण लिया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह चुका दिया था। ऋण लेने के समय कंपनी में उनके और उनके पति के आधार कार्ड व वोटर कार्ड के दस्तावेज जमा किए गए थे। उन्होंने बताया कि फरवरी 2025 में खटीमा स्थित बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन करने पर उन्हें जानकारी हुई कि एससीएनएल खटीमा शाखा में उनके नाम पर 45 हजार रुपये का ऋण चल रहा है। इस संबंध में उन्होंने शाखा प्रबंधक से संपर्क किया। उन्हें पता चला कि शाखा प्रबंधक और कर्मचारियों ने उमरुखुर्द निवासी मेराज बेगम और उसके पति अब्दुल हसन के साथ मिलकर कथित रूप से उनके और उनके पति के आधार कार्ड व वोटर कार्ड के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मेराज बेगम के नाम पर 45 हजार रुपये का ऋण जारी कर दिया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मामले में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

काशीपुर में पांच करोड़ से बनाया जाएगा फायर स्टेशन

काशीपुर। औद्योगिक क्षेत्र व इसके आसपास के क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण के उद्देश्य से अत्याधुनिक अग्निशमन केंद्र बनाया जा रहा है। करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस फायर स्टेशन में हर सुविधाएं होंगी। इसके लिए बजट स्वीकृत हो चुका है। काशीपुर को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। यहां सैकड़ों छोटी–बड़ी औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। वर्तमान में यहां एक फायर स्टेशन मौजूद है लेकिन उसकी इमारत जर्जर हो चुकी है। इसी कारण अब नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। नए अग्निशमन केंद्र में चार गैराज बनाए जाएंगे।

इसमें प्रशासनिक भवन और कर्मचारियों के लिए बैरक भी शामिल होंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यालय कक्ष भी होंगे। फायर ब्रिगेड वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। उपकरण भंडारण कक्ष और एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। भवन का डिजाइन आधुनिक अग्नि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।

औद्योगिक क्षेत्र लगातार हो रहा विकसित

काशीपुर में औद्योगिक क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। यहां संचालित सैकड़ों औद्योगिक इकाइयों के कारण आग लगने का जोखिम बना रहता है। मौजूदा फायर स्टेशन की इमारत काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी है। ऐसे में एक नए और आधुनिक केंद्र की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यह नया केंद्र आग की घटनाओं पर तेजी से काबू पाने में मदद करेगा।

इंटरनेशनल मार्केट में पहुंची उत्तराखंड की मछली

राज्य बनने के बाद पहली बार पांच मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट मछली का निर्यात

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : राज्य निर्माण के बाद पहली बार उत्तराखंड की मछली इंटरनेशनल मार्केट में पहुंची हैं। पिथौरागढ़ जिले की तीन सहकारी समितियों ने राज्य सरकार के सहयोग से नेपाल को पांच मीट्रिक टन मछलियां सप्लाई की हैं। अच्छी खबर ये भी है कि उत्तराखंड आने वाले दिनों में करीब 30 टन मछलियों के निर्यात की तैयारी कर रहा है।

राज्य सचिवालय के मीडिया सेंटर में शुक्रवार को मत्स्य विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रेस कॉफ्रेंस में यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ के धारचूला एवं मुनस्यारी क्षेत्र की तीन मत्स्य जीवी सहकारी समितियों ने ये मछलियां तैयार की थीं। कोल्ड-चेन बनाए रखते हुए मछली को गुजरात के वेरावल भेजा गया, जहां प्रसंस्करण के बाद 23 जून 2026 को नेपाल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका

सफलता पूर्वक निर्यात किया गया। इससे 33 मत्स्य पालकों को लगभग 23.50 लाख की आय प्राप्त हुई है। कैबिनेट मंत्री के अनुसार उत्तराखंड के इस पहले निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु मत्स्य विभाग ने हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग एवं परिवहन के लिए 5.40 लाख की गैप फंडिंग सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि दुबई में आयोजित गल्फ फूड एक्सपो के दौरान अंतरराष्ट्रीय खरीदारों एवं हितधारकों से स्थापित संपर्कों का यह सकारात्मक परिणाम है। विभाग अब यूरोप, मध्य-पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य बाजारों में भी निर्यात की संभावनाओं पर कार्य कर रहा है। इस क्रम में आने वाले दिनों में करीब 30 टन मछली का निर्यात विदेशों में किए जाने की तैयारी की जा रही है। इस मौके पर निदेशक मत्स्य चंद्र सिंह धर्मशक्तू उपस्थित रहे।

मत्स्य क्षेत्र का दायरा बढ़ा, निरंतर हो रही प्रगति

राज्य में मत्स्य क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है। विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि वर्ष 2022 तक जहां राज्य में मात्र 10,011 मत्स्य पालक थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 15,657 हो गई है। इनमें 3,584 महिला मत्स्य पालक शामिल हैं। मत्स्य उत्पादन वृद्धि दर वर्ष 2012-17 में जहां मात्र दो प्रतिशत थी, वह बढ़कर वर्ष 2022-26 में 11 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2026-27 में राज्य अंतर्गत 11,805 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ, जिसका मूल्य लगभग 165 करोड़ है।

विभाग का बजट भी बढ़ा, नौकरी के अवसर भी

मत्स्य विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुसार, मत्स्य विभाग का वार्षिक बजट वर्ष 2021-22 में 55.76 करोड़ से बढ़ कर वर्ष 2026-27 में 261.41 करोड़ हो गया है। पिछले चार वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में 5,646 मत्स्य पालकों हेतु स्वरोजगार के अवसर सृजित किए गए। विभाग में 33 नियमित नियुक्तियां की गई हैं।

साठ वर्ष से पुराने जर्जर भवन में पढ़ने के लिए को मजबूर छात्र

चिन्यालीसौड़। करगिल शहीद दिनेश चंद कुमांई राजकीय इंटर कॉलेज जागत का संचालन विगत 43 वर्षों से करीब साठ वर्ष पुराने राजकीय जूनियर हाईस्कूल के भवन में किया जा रहा है। इसमें कई कमरे जर्जर हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जर्जर कमरों को ध्वस्त कर नया भवन बनाया जाए।

अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगमोहन पंवार, राजेश रावत, मनवीर चौहान, लक्ष्मण कैंतूरा का कहना है कि जोगत में राजकीय जूनियर हाईस्कूल के भवन का निर्माण 1965 में किया गया था। क्षेत्र में इंटर कॉलेज स्वीकृत होने के बाद 1982 से विद्यालय का संचालन जूनियर हाईस्कूल के भवन में किया जा रहा है।

वर्तमान में विद्यालय के करीब 130 छात्र–छात्राएं करीब साठ वर्ष पुराने जर्जर भवन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोग कई बार जर्जर हो चुके भवनों

को तोड़कर वहां पर नए भवन की मांग कर चुके हैं लेकिन इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। कहा कि विद्यालय का नाम करगिल शहीद दिनेश चंद कुमांई के नाम पर रखा गया है। उनके परिजन भी कई बार शासन–प्रशासन से इस विद्यालय के भवन निर्माण की मांग कर चुके हैं।

आयोग ने समूह–ग की दो परीक्षाओं की तिथियां बदलीं

देहरादून : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने समूह–ग की दो परीक्षाओं की तिथि बदल दी है। एक परीक्षा की तिथि तय करते हुए कुल चार भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं अगस्त और सितंबर माह में कराई जाएंगी।आयोग के सचिव एनएस डुंगरियाल की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक भर्ती की परीक्षा–23 अगस्त को प्रदेशभर में कराई जाएगी। इसी प्रकार, पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती की परीक्षा जो 12 जुलाई को होनी थी, अब छह सितंबर को कराई जाएगी। विशेष तकनीकी अर्हता वाले पदों की भर्ती परीक्षा जो 28 जून को होनी थी, वह अब 14 सितंबर को होगी। सहायक लेखाकार परीक्षा 23 अगस्त को ही प्रस्तावित है। इन परीक्षाओं के हिसाब से आयोग ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है।

जानकीचट्टी में अव्यवस्था से स्थानीय लोग परेशान

बड़कोट। यमुनोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव जानकीचट्टी में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों और व्यवसायियों ने सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि बस पार्किंग और आसपास के क्षेत्रों में घोड़े–खच्चरों, डंडी–कंडी मजदूरों और उनके संचालकों का अनियंत्रित जमावड़ा श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का सबब बन रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्किंग क्षेत्र में घोड़े–खच्चर संचालक और डंडी–कंडी मजदूर यात्रियों को सेवाओं के लिए आकर्षित करने की होड़ में लगातार आवाजाही और आवाज लगाते रहते हैं। इससे कई बार भीड़ और अफरा–तफरी जैसी स्थिति बन जाती है। भाजपा नेता एवं होटल व्यवसायी संदीप राणा ने जिला पंचायत की ओर से संचालित कुली एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यात्रा पड़ाव पर बढ़ती अव्यवस्थाएं यमुनोत्री धाम की छवि को प्रभावित कर रही है। राणा ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान देश–विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं। ऐसे में यात्रा पड़ावों पर अनुशासन, भीड़ प्रबंधन और सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने पार्किंग क्षेत्र, घोड़ा–खच्चर संचालन और डंडी–कंडी सेवाओं के लिए सख्त व्यवस्था लागू करने की मांग की। वहीं, कुली एजेंसी से जुड़े शरत सिंह चौहान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस वर्ष व्यवस्थाएं पिछले वर्षों की तुलना में अधिक बेहतर हैं।

पर्यावरण संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता : चौहान

जयन्त प्रतिनिधि। देहरादन : पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में आयोजित दो दिवसीय पूर्व छात्र सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि यदि प्रतिदिन पौधा लगाना संभव न हो, तो कम से कम अपने जन्मदिन पर अवश्य एक पौधा लगाएं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय भारतीय कृषि के इतिहास का गौरवशाली केंद्र है, जिसने देश को वैज्ञानिक, नीति-निर्माता, कृषि उद्यमी तथा उत्कृष्ट मानव संसाधन प्रदान कर कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। श्री चौहान ने पंतनगर विश्वविद्यालय को परंपरा, आधुनिकता और अनुसंधान का त्रिवेणी संगम बताते हुए कहा कि देश आज लगभग 377 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है। देश के अन्न भंडार पूरी तरह भरे हुए हैं तथा चावल उत्पादन में भारत, चीन को पीछे छोड़कर विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि गेहूं का उत्पादन

भी अधिशेष है तथा भारतीय गेहूं एवं बासमती चावल की मांग विश्वभर में लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि मंत्री के रूप में धरातल से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है और उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने पंतनगर में विद्यार्थियों एवं विशेषज्ञों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि वे पंतनगर सिखाने नहीं, बल्कि सीखने आए हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय ने केवल डिग्रियां नहीं बांटीं, बल्कि देश को वैज्ञानिक, नीति-निर्माता, उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ता तथा कृषि उद्यमी दिए हैं, जिन्होंने भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि उत्पादों से संबंधित जितने भी अंतरराष्ट्रीय समझौते किए गए हैं, वे किसानों और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर किए गए हैं। उन्होंने दोहराया कि विकसित भारत के निर्माण का संकल्प तभी साकार होगा, जब कृषि विकसित होगी और किसान समृद्ध होंगे। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक शिव अरोरा, त्रिलोक सिंह चीमा, बंशीधर भगत, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, हुकम सिंह कुंवर, रणजीत सिंह नामधारी, सचिव डॉ. एस. एन. पांडे, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, कुलसचिव दीपा विनय सहित अनेक अधिकारी एवं पूर्व छात्र उपस्थित रहे।

फल एवं विविध कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा दें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारंपरिक फसलों के संरक्षण पर बल देते हुए फल एवं विविध कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। साथ ही उन्होंने कृषि उत्पादन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों एवं विशेषज्ञों की समिति बनाकर ठोस सुझाव देने का आह्वान किया, ताकि उन पर गंभीरता से विचार किया जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पर्वतीय कृषि आज छोटे एवं बिखरे खेतों, जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान, युवाओं के पलायन, सीमित बाजार पहुंच तथा जलवायु परिवर्तन जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। इन समस्याओं का समाधान केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और सामूहिक सहभागिता से संभव है। उन्होंने पूर्व छात्रों से आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, कृषि प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, डिजिटल मार्केटिंग तथा कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में किसानों और युवाओं का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया।

भाजपा—कांग्रेस में टिकट पाने की दौड़ में कई चेहरे

देहरादून : भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली डोईवाला विधानसभा में बृजभूषण गैरोला विधायक हैं लेकिन यहां की विरासत संभालने के लिए भाजपा के कई दावेदार मैदान में जोर आजमाइश करने लगे हैं। संगठन अपने वर्तमान विधायक पर ही भरोसा करेगा या किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है लेकिन टिकट की दौड़ दिलचस्प होने वाली है। इस सीट पर संबंधित दावेदारों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। भाजपा में वैसे तो तमाम दावेदार सामने हैं लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं, जो अपनी दावेदारी पूरे दमखम के साथ पेश कर रहे हैं। इनमें वर्तमान विधायक गैरोला के अलावा भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रूचि भट्ट, कर्नल अजय कोठियाल, जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल की सक्रियता से उनकी दावेदारी झलक रही है। कई और नेता यहां किसी न किसी रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे

हैं। डोईवाला विधानसभा वैसे तो भाजपा का गढ़ रही है। यहां पांचों विधानसभा चुनावों में भाजपा को ही जीत मिली। केवल 2014 के उपचुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। 2002 में यहां भाजपा के त्रिवेंद्र रावत ने कांग्रेस के विरेंद्र मोहन उनियाल को 1536 मतों के अंतर से हराया था। 2007 के चुनाव में भाजपा के त्रिवेंद्र रावत ने कांग्रेस के विरेंद्र मोहन उनियाल को 14,127 मतों के अंतर से हराया। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट को 1272 मतों से हराया। इसके बाद निशंक के लोकसभा चले जाने से यह सीट खाली हो गई।

सुबह झील में उतराता मिला मनीष का शव

नैनीताल झील में शुक्रवार सुबह 45 वर्षीय मनीष का शव उतराता हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव को झील से निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुक्रवार की सुबह ठंडी सड़क से गुजर रहे लोगों की नजर झील में शव पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को झील से बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों के अनुसार बृहस्पतिवार देर शाम मनीष ने घर पर फोन कर गलत कदम उठाने की बात कही थी। सूचना मिलने के बाद परिजनों और पुलिस ने रातभर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। शुक्रवार सुबह उसका शव झील में उतराता मिला।

सोलर पंपिंग योजना बंद पड़ने से रोपाई का संकट

उत्तरकाशी। पिछले 25 वर्षों से हर बरसात में जलभराव की त्रासदी झेल रहे जोशियाड़ा के कालेश्वर मंदिर मार्ग क्षेत्र के लोगों का सब्र अब जवाब देने लगा है। बार–बार ज्ञापन, शिकायतों और आश्वासनों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से नाराज स्थानीय लोग शनिवार को जिला प्रशासन के खिलाफ विशाल जनाक्रोश रैली निकालेंगे।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि वर्षों से जलभराव के कारण बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का जीवन प्रभावित हो रहा है लेकिन प्रशासनिक स्तर पर केवल आश्वासन ही मिले हैं। स्थानीय सभासद सुनीता नेगी, विजय राज, आशीष नेगी आदि क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि कालेश्वर मंदिर मार्ग पर जलभराव की समस्या को लेकर गत कई वर्षों से जिला प्रशासन, एडीएम कार्यालय

और संबंधित विभागों को लगातार ज्ञापन दिए जाते रहे हैं।

बीती 17 जून को भी उपजिलाधिकारी भटवाड़ी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि हर वर्ष बरसात के दौरान सड़कें जलमग्न हो जाती हैं जिससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

कई बार प्रशासन की ओर से संयुक्त समितियां भी गठित की गईं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। जलभराव की स्थायी व्यवस्था की मांग को लेकर शनिवार को महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण, जोशियाड़ा से कलेक्ट्रेट परिसर तक विशाल जनाक्रोश रैली निकाली जाएगी। चेतावनी दी है कि यदि इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो धरना–प्रदर्शन और आवश्यकता पड़ने पर अनशन भी किया जाएगा।

जयन्त

संस्थापक : नरेन्द्र उनियाल स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस बदरीनाथ मार्ग, कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से मुद्रित तथा बदरीनाथ मार्ग, कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित।

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र कोटद्वार, (गढ़वाल) उत्तराखण्ड होगा।

CONT. 9412081969
PRGI NO. 35469/79

शिवम की कहानी: ऐसी की वापसी और बन गए दो बार के विश्व चैंपियन

ओवरवेट होने के कारण छोड़ा था क्रिकेट

मुंबई, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक ऑलराउंडर शिवम दुबे आज उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, जिन पर टीम मुश्किल परिस्थितियों में भरोसा करती है। बड़े-बड़े छक्के लगाने की उनकी क्षमता और जरूरत पड़ने पर उपयोगी गेंदबाजी ने उन्हें सीमित ओवरों की टीम का अहम सदस्य बना दिया है। लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा।

26 जून 1993 को मुंबई में जन्मे शिवम दुबे का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही का रहने वाला है। बचपन से ही क्रिकेट के प्रति उनका जुनून था और उन्होंने कम उम्र में ही इस खेल को अपना लक्ष्य बना लिया था। हालांकि, 14 साल की उम्र में उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसने उनके क्रिकेट करियर पर लगभग विराम लगा दिया।

आर्थिक तंगी के कारण नियमित प्रशिक्षण और फिटनेस पर ध्यान देना मुश्किल हो गया। धीरे-धीरे उनका वजन काफी बढ़ गया और उन्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ा। कई खिलाड़ियों के लिए ऐसी स्थिति करियर का अंत साबित होती है, लेकिन शिवम ने हार मानने के बजाय वापसी की तैयारी शुरू कर दी।

पांच साल बाद मैदान पर लौटे और बदल दी किस्मत

करीब पांच साल तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद शिवम दुबे ने जब वापसी की तो उनका लक्ष्य सिर्फ टीम में जगह बनाना नहीं, बल्कि खुद को साबित करना था। उन्होंने कड़ी मेहनत कर फिटनेस हासिल की और मुंबई की अंडर-23 टीम में जगह बनाई।इसके बाद उनका करियर तेजी से आगे बढ़ा। जनवरी 2016 में उन्होंने मुंबई के लिए टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया। 2017 में प्रथम श्रेणी और लिस्ट-ए क्रिकेट में भी डेब्यू किया। घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद उभरते ऑलराउंडरों में शामिल कर दिया।

आईपीएल ने बदली जिंदगी

शिवम दुबे को आईपीएल 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मौका दिया, लेकिन उनके करियर में असली बदलाव 2022 में आया, जब वह चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े। महेंद्र सिंह धोनी की टीम में उन्हें अपनी भूमिका स्पष्ट मिली। मध्यक्रम में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मैच फिनिश करने की कला विकसित की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीएसके के लिए उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया। 2022 में 289 रन, 2023 में 418 रन, 2024 में 396 रन, 2025 में 357 रन और 2026 में 270 रन बनाकर टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाई। आईपीएल में वह अब तक 92 मैचों में 2129 रन और 10 अर्धशतक अपने नाम कर चुके हैं।

रोहित शर्मा का भरोसा, सूर्यकुमार की टीम के भी बने हीरो

घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद शिवम दुबे को भारतीय टीम में लगातार मौके मिलने लगे। कप्तान रोहित शर्मा ने उनकी ताकत को पहचाना और उन्हें मध्यक्रम में आक्रामक बल्लेबाज की भूमिका सौंपी। शिवम ने इस भरोसे को सही साबित किया। उन्होंने बीच के ओवरों में तेजी से रन बनाकर कई मैचों का रुख बदला। गेंदबाजी में भी जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम को संतुलन दिया। वह 2024 में रोहित शर्मा और 2026 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के अहम सदस्य रहे।

विश्व कप के बड़े मुकाबलों में निभाई अहम भूमिका

बड़े खिलाड़ियों की पहचान बड़े मैचों से होती है और शिवम दुबे ने यह कई बार साबित किया। टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में 27 रन बनाकर भारत की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद 2026 विश्व कप के सेमीफाइनल में उन्होंने 25 गेंदों पर 43 रन की तेजतर्रार पारी खेली। फाइनल में भी उन्होंने महज आठ गेंदों पर 26 रन बनाकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। इन पारियों ने साबित किया कि दबाव वाले मुकाबलों में भी वह टीम के लिए मैच विनर बन सकते हैं।शिवम दुबे ने तीन नवंबर 2019 को भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। अब तक वह 64 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 48 पारियों में 16 बार नाबाद रहते हुए 991 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 154.12 रहा है। इसके अलावा उन्होंने 31 विकेट भी अपने नाम किए हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने चार मैच खेलते हुए 43 रन बनाए हैं और एक विकेट भी लिया है।

महिला टी-20 विश्वकप

ब्रिट्स का शतक, दक्षिण अफ्रीका ने नीदरलैंड्स को 88 रन से हराया

ब्रिस्टल, एजेंसी। महिला टी20 विश्व कप 2026 के 24वें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड्स के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की। काउंटी ग्राउंड पर खेले गए मैच में प्रोटियाज टीम से मिले 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स की टीम 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 120 रन ही बना सकी।

दक्षिण अफ्रीका ने 88 रनों की बड़ी जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी दावेदारी को मजबूत कर लिया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका, दोनों के छह-छह अंक हैं। इस जीत से दक्षिण अफ्रीका ने अपने नेट रन रेट में भी काफी सुधार किया है। भारत की टेंशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि उसका अगला मुकाबला यानी ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम से है, जबकि दक्षिण अफ्रीका को बांग्लादेश से भिड़ना है। भारत को हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। साथ ही यह मनाना होगा कि या तो दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश से हार जाए या फिर नेट रन रेट भारत से बेहतर नहीं कर पाए।

नीदरलैंड्स की पारी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम को फेबे मोलकेनबोअर और सान्या खुराना ने सधी हुई शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 58 रन जोड़े। सान्या ने 30 गेंदों का सामना करते हुए छह चौकों की मदद से 36 रन बनाए। वहीं, फेबे ने 41 रनों का योगदान दिया। नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरीं स्टेरे कालिस ने 26 रन बनाए, जबकि बैबेट डी लीडे 11 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।

इसके बाद नीदरलैंड्स ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए और टीम मुश्किल से 100 रनों का आंकड़ा पार कर सकी। नीदरलैंड्स की छह बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक पार करने में नाकाम रहीं। गेंदबाजी में साउथ अफ्रीका की ओर से अयाबोंगा खाका ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 19 रन देकर तीन विकेट चटकाए। वहीं, क्लोई ट्रायोन ने चार ओवर के स्पेल में 16 रन देकर दो विकेट निकाले।

दक्षिण अफ्रीका की पारी

इससे पहले, दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में एक विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 208 रन लगाए। टीम को कप्तान एल वोल्वार्ट और ताजमिन ब्रिट्स ने शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 13.3 ओवर में 121 रन जोड़े। वोल्वार्ट ने 36 गेंदों में छह चौकों की मदद से 45 रन बनाए।वहीं, ब्रिट्स ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। ब्रिट्स ने 69 गेंदों में 114 रनों की नाबाद पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 15 चौके और तीन छक्के लगाए। वहीं, अंत के ओवरों में एनेरी डेर्कसेन ने महज 16 गेंदों में तीन चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 37 रन बनाए। गेंदबाजी में नीदरलैंड्स की तरफ से एकमात्र विकेट हन्ना लैंडहीर ने चटकाया।

हम तेजी से लक्ष्य हासिल करना चाहते थे

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि कहां है सुधार की जरूरत

मैनचेस्टर, एजेंसी। महिला टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को भारतीय टीम ने जिंदा रखा है। ग्रुप ए के मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को पांच विकेट से हराया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताई है, लेकिन उन्होंने माना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले फील्डिंग अभी भी एक बड़ी चिंता का विषय है।

बांग्लादेश को आसानी से हराया

ओल्ड टैफर्ड के मैदान पर बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 136 रन लगाए। हालांकि, भारतीय टीम ने शेफाली वर्मा की अर्धशतकीय पारी के बूते 137 रनों के लक्ष्य को 16.5 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया। शेफाली ने 34 गेंदों में 53 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं, गेंदबाजी में राधा यादव ने तीन विकेट चटकाए।

मैच के बाद हरमनप्रीत कौर ने कहा कि टीम का लक्ष्य मैच को जल्दी खत्म करना था ताकि नेट रन रेट में भी सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि भारत ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन अगर टीम थोड़ा और जल्दी लक्ष्य हासिल कर लेती तो और बेहतर होता। फिर भी दो-तीन ओवर पहले मैच खत्म करना टीम के लिए सकारात्मक बात रही। जीत के बावजूद भारतीय कप्तान अपनी टीम की फील्डिंग से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखीं। उन्होंने कहा कि टीम लगातार फील्डिंग पर मेहनत कर रही है, लेकिन इस मैच में भी कई आसान कैच छूट गए। इन गलतियों की वजह से बांग्लादेश की बल्लेबाजों को बड़ी साझेदारी बनाने का मौका मिला और टीम उम्मीद से ज्यादा रन बनाने में सफल रही।

हरमनप्रीत ने कहा कि फील्डिंग ऐसी चीज है, जिसमें टीम को जल्द सुधार करना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले अगले मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी और ऐसी गलतियां नहीं दोहराएंगी। उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों से कैच छूटे, वे टीम के सबसे अच्छे फील्डरों में शामिल हैं। ऐसे में किसी एक खिलाड़ी को दोष देना सही नहीं होगा। कप्तान ने कहा कि कभी-कभी मैदान पर ऐसे हालात बन जाते हैं, जिन्हें पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जरूरी बात यह है कि खिलाड़ी लगातार अभ्यास करें और अपनी गलतियों से सीख लें।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच पर है ध्यान

हरमनप्रीत ने बताया कि टीम का पूरा ध्यान अब अगले मुकाबले पर है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी मैदान पर अधिक समय बिताकर कैच पकड़ने और फील्डिंग में सुधार करने की कोशिश करेंगे ताकि बड़े मुकाबलों में कोई आसान मौका हाथ से न निकल जाए। भारतीय कप्तान ने टीम चयन को लेकर भी अपनी रणनीति साझा की। उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट किसी एक तय प्लेइंग इलेवन पर निर्भर नहीं है। हर मुकाबले में विरोधी टीम की ताकत, कमजोरियों और पिच की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अंतिम एकादश का चयन किया जाता है।

सेमीफाइनल के लिए हर हाल में चाहिए होगी जीत

भारतीय टीम को ग्रुप स्टेज के अपने अगले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। हरमनप्रीत ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय टीम ऐसे मुकाबलों का इंतजार करती है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भारत की पसंदीदा विपक्षी टीम बताया।हरमनप्रीत ने कहा, हम जानते हैं कि हर मैच जीतना जरूरी है, और कभी-कभी जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होतीं, तो आपको अपना बेस्ट देना होता है। ऐसे में मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम इस मैच को जीतने में सफल रहते हैं, तो इससे हमें बहुत आत्मविश्वास मिलेगा। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली पिछली जीत से भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। उस जीत ने खिलाड़ियों का भरोसा मजबूत किया और कई मानसिक बाधाएं भी दूर कीं।

जर्मनी को हरा इतिहास रच गया इक्वाडोर पूरे देश में जश्न, अवकाश घोषित किया

न्यू जर्सी, एजेसी। फीफा विश्व कप 2026 से एक बेहद चौंकाने वाली और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। ग्रुप-ई के अपने आखिरी मुकाबले में अंडरडॉग मानी जा रही इक्वाडोर की टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए चार बार की विश्व चैंपियन जर्मनी को 2-1 से धूल चटा दी है। स्थानीय समयानुसार गुरुवार (25 जून) को न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मैच में जीत दर्ज कर इक्वाडोर ने विश्व कप के नॉकआउट स्टेज में जगह पक्की कर ली है। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने देश में राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा कर दी है।

इस महाविजय के बाद राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक और गर्व से भरी पोस्ट साझा की। उन्होंने टीम की आलोचना करने वालों को करारा जवाब देते हुए खिलाड़ियों और मुख्य कोच सेबेस्टियन बेकासेसे का आभार जताया।

राष्ट्रपति नोबोआ ने लिखा 'खिलाड़ियों और कोच को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने तमाम आलोचनाओं, अपमान और कठिन दौर से गुजरने के बावजूद शानदार वापसी की और पूरे देश को यह असीम खुशी दी। कल (शुक्रवार) देश में छुट्टी रहेगी! इक्वाडोर

अमर रहे। '

ऐसे पलटा मैच का पासा

इक्वाडोर के लिए यह राह आसान नहीं थी। टीम को अपने पहले मैच में आइवरी कोस्ट से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि कुराकाओ के खिलाफ दूसरा मैच गोलरहित ड्रा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी की टीम पहले ही नॉकआउट के लिए क्वालीफाई कर चुकी थी और मैच में जीत की प्रबल दावेदार थी।

मैच की शुरुआत में जर्मनी ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। फ्लोरियन विर्ट्ज़ के पास पर लेरॉय साने ने मैच का पहला शॉट सीधे गोल पोस्ट के भीतर दागकर जर्मनी को शुरुआती बढ़त दिला दी। साने ने बड़ी ही आसानी से गेंद को इक्वाडोर के गोलकीपर हर्नान गैलिंडेज को छकाते हुए निचले बाएं कोने में डाल दिया। इस गोल के तुरंत बाद इक्वाडोर के खिलाड़ियों ने फाउल की अपील की। रीप्ले में भी यह देखा गया कि गोल से ठीक पहले जर्मनी के अलेक्सांद्र पाव्लोविच का पैर इक्वाडोर के मिडफील्डर प्रेडो विटे के सिर पर लगा था, लेकिन अंपायर ने इसे नजरअंदाज कर दिया।

निल्सन एंगुलो का जादुई गोल

शुरुआती झटका लगने के बावजूद इक्वाडोर ने हिम्मत नहीं हारी। टीम ने पूरे दमखम और आक्रामकता के साथ वापसी की। मैच के 9वें मिनट में ही निल्सन एंगुलो ने मिडफील्ड से मिले एक ढीले पास को लपका और मैनुअल न्युएर जैसे दिग्गज गोलकीपर को छकाते हुए एक बेहद दमदार लॉन्ग-रेंज शॉट लगाकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद पहले हाफ तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं।

मैच का सबसे निर्णायक क्षण 77वें मिनट में आया। दाएं छोर से मिले एक कॉर्नर पर केविन रोड्रिगेज ने हवा में उछलकर गेंद को गोल पोस्ट की तरफ फ्लिक किया, जहां खड़े गोंजालो प्लाटा ने बिना कोई गलती किए फुर्ती से गेंद को नेट के अंदर धकेल दिया। इस गोल के होते ही स्टेडियम में मौजूद इक्वाडोर के फैंस और डगआउट में बैठे खिलाड़ी खुशी से झूम उठे।

सांस रोक देने वाला रोमांच

2-1 की बढ़त लेने के बाद इक्वाडोर की टीम पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में आ गई। मैच के अंतिम क्षणों और 7 मिनट के इंजरी टाइम में जर्मनी ने बराबरी का गोल दागने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इक्वाडोर के डिफेंस ने चट्टान की तरह डटकर जर्मनी के हर वार को नाकाम कर दिया। आखिरकार, अंतिम सीटी बजने के साथ ही इक्वाडोर ने 2-1 से मैच अपने नाम कर लिया।

सिंधुश्री ने पोल वॉल्ट में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, अनिमेष-उन्नथी ने किया क्वालिफाई

नई दिल्ली। 65वीं नेशनल सीनियर इंटर-स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुरुवार को कई भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2026 एशियन गेम्स के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की। प्रतियोगिता के दौरान सिंधुश्री ने महिलाओं की पोल वॉल्ट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जबकि स्प्रिंटर्स अनिमेष कुजूर और उन्नथी बोल्लांडा ने एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मानक हासिल कर लिया।

महिलाओं की पोल वॉल्ट स्पर्धा में सिंधुश्री ने 4.25 मीटर की ऊंचाई पार कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने रोजी मीना पॉलराज के 4.21 मीटर के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यह रिकॉर्ड अक्तूबर 2022 में बेंगलुरु में आयोजित इंडियन चैंपियनशिप के दौरान बनाया गया था। इसी स्पर्धा में बरानिका फ्लैंगोवन ने 4.20 मीटर की छलांग लगाकर एशियन गेम्स 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया।पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में अनिमेष कुजूर ने सेमीफाइनल में 20.87 सेकंड का समय निकालकर एशियन गेम्स का क्वालिफिकेशन मानक हासिल किया। इसके बाद फाइनल में उन्होंने 20.74 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में उन्नथी बोल्लांडा ने 23.658 सेकंड का समय निकालते हुए एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। वहीं हरिता ने 23.55 सेकंड का समय लेकर क्वालिफिकेशन मानक पार किया और जापान में होने वाले महाद्वीपीय खेलों का टिकट हासिल किया।

वापसी के लिए तैयार सेरेना विलियम्स, पहले दौर में जॉइंट से सामना; जोकोविच को मिली सातवीं वरीयता

सात बार की विंबलडन एकल चैंपियन सेरेना विलियम्स सोमवार से शुरू हो रहे इस ग्रैंडस्लैम के पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया की 20 वर्षीय माया जॉइंट से भिड़ेंगी। यह लगभग चार वर्षों के अंतराल के बाद इस टूर्नामेंट में उनका पहला एकल मुकाबला होगा। इस 44 वर्षीय दिग्गज को घसियाले कोर्ट पर खेले जाने वाले टूर्नामेंट के लिए लिए वाइल्ड कार्ड मिला है। वह एकल के अलावा अपनी बड़ी बहन वीनस विलियम्स (46) के साथ युगल स्पर्धा में भी हिस्सा लेंगी।

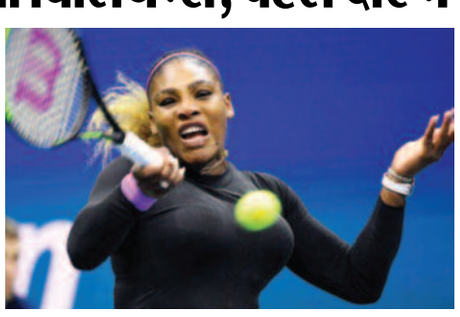

सेरेना की टेनिस में वापसी की शुरुआत दो युगल अभ्यास मुकाबलों से हुई थी, लेकिन रविवार को ऑल इंग्लैंड क्लब द्वारा उनके एकल खेलने की घोषणा के साथ उनकी वापसी को नई गति मिल गई। सेरेना ने अपना पिछला एकल मुकाबला 2022 के यूएस ओपन में खेला था, जहां उन्हें तीसरे दौर में अजला टोमल्यानोविच के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। उस समय उन्होंने संन्यास शब्द का इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए कहा था कि वह टेनिस से दूर होकर अपने जीवन के नए चरण की ओर बढ़ रही हैं। साल 2023 में उनकी दूसरी बेटी का जन्म हुआ था। विम्बलडन में सेरेना पिछला मुकाबला 2022 में खेली थी। उन्हें तब पहले दौर में ही तत्कालीन विश्व नंबर 115 हार्मनी टैन ने पराजित किया था।पुरुष एकल वर्ग में मौजूदा चैंपियन और विश्व नंबर एक यानिक सिनर शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं, जबकि महिला वर्ग में एरीना सबालेंका को शीर्ष वरीयता मिली है। विंबलडन की वरीयताएं एटीपी और डब्ल्यूटीए रैंकिंग के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।